महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्षः29 अंकः195 दिनांकः20-11-2024 बुधवार मूल्यः1 रूपया 50 पैसा पृष्ठः4 वडोदरा M

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद नकदी, शराब और अन्य सामग्री सहित कुल 660 करोड़ रुपये मूल्य के वोट जब्त किए गए,

चुनाव से पहले पैसे बांटना, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े पर चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर

पांच करोड़ रुपए बांटने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

मुंबई (ईएमएस)। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले पैसे बांटने को लेकर हंगामा हो गया है। यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर मतदाताओं को पांच करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा है। आरोपों का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने तावड़े पर एफआईआर दर्ज करवाई है। उनके अलावा बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि, तावड़े ने पैसे बांटने के आरोपों को गलत बताया है। मामले के अनुसार हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी (बीवीए) ने आरोप लगाया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने वोटर्स को पैसे बांटें। बीवीए ने कहा- तावड़े मंगलवार को पांच करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके की एक होटल पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजन नाइक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे। यहां उनकी मीटिंग चल रही थी। बीवीए के मुताबिक होटल में मतदाताओं को पैसे बांटे गए। जानकारी मिलने पर हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी होटल पहुंचे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। क्षितिज ठाकुर नालासोपारा से पार्टी उम्मीदवार भी हैं। होटल के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें बीवीए कार्यकर्ता नोट लिए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा-जोखा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए

तावड़े बोले- मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गया था। खुद पर लगे पैसे बांटने के आरोप पर विनोद तावड़ ने कहा- नालासोपोरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। चुनाव के दिन की आचार संहिता की 12 बातें बताने के लिए मैं वहां पहुंचा था। हमारी सामने वाली पार्टियों को लगा कि मैं वहां पैसे बांटने पहुंचा हूं। इन आरोप की चुनाव आयोग और पुलिस जांच करें। मैं 40 साल से पार्टी में हूं। सभी मुझे जानते हैं। मैं भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

आखिर सरकार का भ्रष्टाचार उजागर

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा- आखिर सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो गया। विरार के एक होटल में पैसे बांटते रंगे हाथ पकड़े गए बीजेपी के केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए विनोद तावड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखने और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना जरूरी है।

मारे गए कुकी उग्रवादियों के समर्थन में प्रदर्शन

-मणिपुर में सैकड़ों लोग खाली ताबूत लेकर सडक़ों पर उतरे

नई दिल्ली/इंफाल(ईएमएस)। मणिपुर में 11 नवंबर को सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों के लिए न्याय की मांग करते हुए कुकी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को भी चुराचांदपुर जिले में सैकड़ों लोगों ने 10 खाली ताबूत लेकर मार्च निकाला।

मणिपुर पुलिस के अनुसार, पिछले हफ्ते जिरिबाम के बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन और पास के जकुराधोर में सीआरपीएफ कैंप पर वर्दीधारी उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दस संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। हालांकि कुकी समुदाय का कहना है कि वे लोग विलेज वॉलंटियर्स थे। यह रैली ज्वाइंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गनाइजेशन ने आयोजित की थी। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों लोग हाथों में पोस्टर लिए शामिल हुए। इन पोस्टर्स पर मारे गए लोगों के लिए न्याय और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रशासन की मांग की गई थी।

मंत्रियों का दबाव, ब्याज दरें घटा सकता है आरबीआई

पीयूष गोयल के बाद वित्तमंत्री ने दिया संदेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ब्याज दरें घटाने के सुझाव के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दरों को लेकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक बड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि भारत के विकास को गति देने के लिए कर्ज की ब्याज दरें कम होनी चाहिए! हालांकि पीयूष गोयल को आरबीआई गवर्नर ने उसी समय जवाब दिया था कि वो इसका सटीक उत्तर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में देंगे। लेकिन अब जिस तरह से वित्त मंत्री ने देश के विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों को सस्ता बनाना बेहद जरूरी बताया है, उससे आरबीआई ब्याज दरों को लेकर गंभीरता से विचार जरूर करेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में छोटे और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं। महंगे कर्ज के चलते नए प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है।

भारत में ब्याज दरें विकसित देशों के मुकाबले अधिक

भारत में फिलहाल बैंकों की कर्ज पर ब्याज दरें विकसित देशों के मुकाबले काफी अधिक हैं। देश में औसतन ब्याज दर 8 से 10 फीसदी तक हैं, वहीं अमेरिका में ये दरें 4 से 5 फीसदी के मध्य हैं, जबकि जापान में लगभग शून्य फीसदी ब्याज दर है। वैसे तो भारत अभी विकासशील देश है और इन देशों की तरह यहां पर ब्याज दरों को नहीं घटाया जा सकता, लेकिन फिर भी भारत को अपनी ब्याज दरों को वैश्विक मानकों के हिसाब से कम करने की जरूरत है। देश के उद्योग जगत ने भी ब्याज दरों में कटौती की मांग करते हुए कहा है कि ब्याज दरें घटाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी के हिसाब से तय होगा।

भारत का सुरक्षित समुद्री नेटवर्क विजन दुनिया में गूंज रहाः मोदी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत का स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित समुद्री नेटवर्क का विजन दुनिया भर में गूंज रहा है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव' समुद्री संसाधनों को राष्ट्रों के विकास के लिए एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देखता है। महासागरों पर यह संवाद नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को और मजबूत करता है और राष्ट्रों के बीच शांति, विश्वास और मित्रता को बढ़ाता है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित हो रहे कार्यक्रम सागर मंथन, द ओशन डायलॉग के लिए अपने संदेश में कही। पीएम मोदी ने कहा, हम 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सागर मंथन जैसे संवाद आम सहमति, साझेदारी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध भविष्य बनाने के लिए अमूल्य हैं। सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से, मुझे विश्वास है कि ये चर्चाएं दूर-दूर तक गूंजेंगी और एक उज्जवल, अधिक जुड़े हुए भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की समुद्री परंपरा लाखों साल पुरानी है और यह दुनिया की सबसे समृद्ध समुद्री परंपराओं में से एक है। लोथल और धोलावीरा के संपन्न बंदरगाह शहर, चोल वंश के बेड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज के कारनामे महान प्रेरणास्त्रोत हैं। महासागर राष्ट्रों और समाजों के लिए एक साझा विरासत हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जीवन रेखा भी हैं।

सभी देशों की समृद्धि समुद्री रास्तों से जुड़ी

मोदी ने कहा, आज, सभी देशों की सुरक्षा और समृद्धि समुद्री रास्तों से जुड़ी हुई है। महासागरों की क्षमता को पहचानते हुए, भारत ने समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले दशक में समृद्धि के बंदरगाह, प्रगति के बंदरगाह और उत्पादकता के बंदरगाह के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हमने अपने बंदरगाहों की क्षमता को दोगुना कर दिया है। बंदरगाह की दक्षता में वृद्धि, टर्नअराउंड समय को कम करने और एक्सप्रेसवे, रेलवे और नदी नेटवर्क के माध्यम से अंत तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के जरिए, हमने भारत की तटरेखा को बदल दिया है। बता दें कि दो दिवसीय इस कार्यक्रम में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और विद्वान एक साथ आए हैं। इतना ही नहीं नाइजीरिया में प्रधानमंत्री के कैंप कार्यालय से भेजे गए संदेश में मानवता के समृद्ध भविष्य की साझेदारी के लिए आम सहमति बनाने हेतु सागर मंथन को सफल बनाने की अपील की गई है।

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा सीटों पर आज मतदान

-4 राज्यों की 15 विधानसभा और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव

मुंबई(ईएमएस)। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 और झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों के साथ ही 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव होंगे। इन 15 में से 13 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने, 1 के निधन और 1 के जेल जाने से ये सीटें खाली हुई हैं। इनमें 2 सीटें स्ट के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियां दो गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा की अगुआई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की भाजपा महायुति का हिस्सा हैं। जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी(एसपी) महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं।

झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 1.23 करोड़ वोटर्स शामिल होंगे। सेकेंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटानागपुर और दो सीटें रांची जिले की है। चुनाव आयोग के मुताबिक, दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 55 महिला उम्मीदवार हैं। 127 करोड़पति हैं, जबकि 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इसी फेज में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बाउरी चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा-शिवसेना का गठबंधन था। तब भाजपा ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थीं। जबकि कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटें मिलीं थीं। भाजपा-शिवसेना आसानी से सत्ता में आ जातीं, लेकिन गठबंधन टूट गया। तमाम सियासी उठापटक के बाद 23 नवंबर, 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले ही 26 नवंबर को दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 28 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने। करीब ढाई साल बाद शिवसेना और उसके एक साल बाद एनसीपी में बगावत हुई और 2 पार्टियां 4 दलों में बंट गईं। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को बढ़त मिली थी।

उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट उड़ाने की धमकी

मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से आया मैसेज

मथुरा (ईएमएस)। उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के वॉट्सएप पर वॉयस मैसेज में मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में सुनवाई भी है। आशुतोष का दावा है- वॉयस मैसेज पाकिस्तान के नंबर से आया है। मथुरा के आशुतोष पांडेय को वॉट्सएप पर सोमवार रात 1:37 से 1:40 बजे के बीच पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे 6 वॉयस मैसेज आए। इसके बाद 2:36 बजे वॉट्सएप कॉल कर धमकी दी गई। आशुतोष श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में पक्षकार हैं। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 4 से 14 सेकेंड तक के 6 धमकी भरे वॉयस मैसेज आए। इसमें कहा- हाईकोर्ट को क्या, तेरे सुप्रीम कोर्ट को भी उड़ा देंगे। तुम्हारे में दम नहीं है। 19 नवंबर को तुझे बताएंगे, बम धमाके करेंगे। हाईकोर्ट में तुझे बम से उड़ा देंगे। मथुरा, दिल्ली, हिंदुस्तान के सभी बड़े मंदिरों को उड़ा देंगे। इसके बाद 3:02 बजे मैसेज आया, जिसमें लिखा- 19 नवंबर की सुबह पहले प्रयागराज स्टेशन और फिर हाईकोर्ट को उड़ाएंगे।

भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मुद्दा उठा

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के मुद्दे पर बातचीत हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के समकक्षों के बीच सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया आदान-प्रदान को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है।

ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से द्विपक्षीय मुलाकात की।

वैश्विक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएं दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और एससीओ ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है। जी20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत के विदेश मंत्री से सहमति व्यक्त की कि भारत-चीन संबंधों का विश्व राजनीति में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता आगे बढ़ने के रास्ते पर कज़ान में सहमत हुए थे। दोनों मंत्रियों ने महसूस किया कि ये जरूरी है कि ध्यान संबंधों को स्थिर करने, मतभेदों को कम करने और अगले कदम उठाने पर होना चाहिए।

देश में ठंड-कोहरे और प्रदूषण का असर...

दिल्ली की हवा रोज 38 सिगरेट, हरियाणा की 25 सिगरेट, यूपी में 8, बिहार में 7 और मप्र में 2 सिगरेट जितनी जहरीली

मप्र की पराली फैला रही दिल्ली में प्रदूषण!

- पंजाब-हरियाणा को मप्र ने छोड़ा पीछे, श्योपुर में सबसे अधिक 489 पराली जलाने की घटनाएं

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर(ईएमएस)। देश में प्रदूषण का स्तर बताने वाले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण पिछले 2 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। 17 नवंबर को एक्यूआई 441 था। 18 नवंबर को सुबह 6 बजे तो एक्यूआई 494 पार कर गया। सीपीसीबी ने इतने एक्यूआई को सीवियर+ कैटेगरी में रखा है। इस हवा में सांस लेने वाला स्वस्थ्य व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। देश में प्रदूषण की स्थिति का आकलन इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली में एक व्यक्ति औसतन 38 सिगरेट जितना धुआं प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा है। वहीं हरियाणा में 25 सिगरेट, यूपी में 8, बिहार में 7 और मप्र में 2 सिगरेट जितना धुआं प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दावा किया कि पराली की घटनाएं केवल पंजाब में कम हुई है। मप्र में सबसे अधिक पराली जलाई जा रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि पंजाब ने घटनाएं कम की हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मप्र की पराली दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है।

देश में सर्वाधिक वन आवरण होने के बाद भी मप्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा का कारण सडक़ की धूल, वाहन और उद्योगों के साथ-साथ पराली है। स्थिति यह हो गई है कि पराली जलाने में मप्र ने पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है। 15 सितंबर से 14 नवंबर तक देश में सर्वाधिक 8,917 पराली जलाने की घटनाएं प्रदेश में दर्ज हुईं। यह बात कृषि अभियांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा जारी पराली जलाने की घटनाओं के सेटेलाइट डेटा से सामने आई है। मप्र में 15 सितंबर से 14 नवंबर 2024 के बीच पराली जलाने की जो घटनाएं सामने आईं उनमें सर्वाधिक 489 श्योपुर में दर्ज की गईं। जबलपुर में 275 घटनाएं हुईं तो ग्वालियर, नर्मदापुरम्, सतना, दतिया जैसे जिलों में लगभग 150-150 घटनाएं दर्ज की गईं। यह डेटा पंजाब व हरियाणा जैसे कृषि में अग्रणी प्रदेशों से भी अधिक है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दावा किया कि पराली की घटनाएं केवल पंजाब में कम हुई है।

मप्र समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट

देश में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में एक-दो दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भरतपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई। हालांकि, देश में सबसे कम विजिबिलिटी (जीरो मीटर) आगरा में दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, यहां आने वाले कुछ दिनों में कोहरा बना रहेगा। उधर, मप्र में भी भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया में घना कोहरा देखने को मिला। इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों में बर्फबारी के कारण मप्र में ठंड बढ़ी है। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सोनमर्ग में सोमवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी मंगलवार सुबह भी जारी रही। इस कारण पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

तमिलनाडु में भारी बारिश

तमिलनाडु के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राज्य कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि वेदारण्यम में सबसे ज्यादा 17.5 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद कोडियाकराई में 13.4 सेमी बारिश हुई। तिरुवरुर में भी भारी बारिश हुई। थिरुथुराईपोंडी में सिर्फ दो घंटों में 7 सेमी बारिश दर्ज की गई। तंजावुर में पट्टुकोट्टई क्लॉक टॉवर और बस स्टेशन सहित कई जगहों पर पानी भर गया।

सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी

मप्र में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार सुबह ग्वालियर में घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी यानी, दृश्यता 500 से 1 हजार मीटर तक दर्ज की गई। रात का पारा 3.9 डिग्री लुढक़कर 12.3 डिग्री पर आ गया, जो सामान्य से नीचे रहा। इस बार नवंबर में पहली बार ग्वालियर में इतनी ठंड पड़ी। दतिया, भिंड, मुरैना, निवाड़ी में भी कोहरे का असर देखने को मिला। इधर, भोपाल में सुबह सर्द हवाएं चलने से लोग ठिठुर गए। यहां हल्का कोहरा भी रहा। हालांकि, पारे में उछाल नहीं आया और यह 14 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में 16.5 डिग्री, उज्जैन में 15.2 डिग्री और जबलपुर में तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार-मंगलवार की रात में पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार-सोमवार की रात की तुलना में पारे में हल्की गिरावट हुई।

उत्तरी हवाएं चलने से बढ़ेगी ठिठुरन

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो गई है। जेट स्ट्रीम हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में उत्तरी हवाएं मप्र में भी आएंगी, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। आने वाले दिनों में पारे में और भी गिरावट हो सकती है। अभी दिन का तापमान औसत 2 डिग्री लुढक़ गया है। वहीं, 15 से अधिक शहरों में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। प्रदेश में ठंड बढऩे के साथ ही स्कूलों की टाइमिंग भी बदल गई है। भोपाल के कई स्कूलों का समय 30 मिनट आगे बढ़ाया गया है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी टाइमिंग बदलेगी।

माल्या-नीरव पर कसेगा शिकंजा!

-पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात में उठाया भगोड़ों का मुद्दा

नई दिल्ली(ईएमएस)। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर ब्रिटेन जल्द एक्शन ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने ये मुद्दा ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के सामने उठाया है। जी-20 शिखर सम्मेलन में ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने माइग्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया तेज करने की जरूरत पर सहमति जताई।

बता दें कि पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर के बीच यह पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ने उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई भी दी तो वहीं स्टार्मर ने पीएम को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

बता दें कि भारतीय बिजनेसमैन नीरव दीपक मोदी एक भारतीय मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के केस में भगोड़ा है। उसपर इंटरपोल और भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक के 2 अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के एक केस में नीरव मोदी की जांच की जा रही है।

मार्च 2018 में नीरव मोदी के यूके में होने की सूचना मिली थी, जहां उसने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया था। जून 2019 में स्विस अधिकारियों ने संपत्ति के साथ नीरव मोदी के स्विस बैंक खातों में मौजूद कुल 6 मिलियन स् डॉलर को सील कर दिया था। नीरव मोदी का परिवार कई पीढ़ियों से हीरे के कारोबार में है।

वहीं, विजय विट्टल माल्या भी एक भारतीय बिजनेसमैन और पूर्व सांसद है। माल्या पर किंगफिशर कंपनी के डूबने को लेकर भारतीय कानून के तहत विलफुल डिफॉल्टर होने का आरोप है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, हेराफेरी के आरोप शामिल हैं।

अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को त्र40 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को चार महीने जेल की सजा सुनाई और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। शीर्ष अदालत ने माल्या को जेल की सजा सुनाते हुए चार सप्ताह के भीतर 8 प्रतिशत ब्याज के साथ 4 करोड़ डॉलर सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा प्राधिकरण को जमा करने के लिये भी कहा था।

थाईलैंड में एअर इंडिया के 100 यात्री 80 घंटे से फंसे

बैंकॉक (ईएमएस)। थाईलैंड के फुकेत में तकनीकी खराबी के चलते एअर इंडिया के 100 यात्री 80 घंटे से फंसे हुए हैं। ये यात्री एअर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से विमान उड़ान नहीं भर पा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली जा रही फ्लाइट तीन बार टल चुकी है। एक बार उड़ान भी भरी, लेकिन ढाई घंटे बाद ही इसे फुकेत एयरपोर्ट पर लौटा लिया गया। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियां बताई हैं। यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट 16 नवंबर की रात दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी का हवाला देकर छह घंटे के लिए टाल दिया गया।

एलआईसी की तकनीकी खामी पर हुई भाषाई राजनीति, तमिलनाडु के नेताओं ने खड़ा किया सियासी बवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की वेबसाइट पर 'भाषा पृष्ठ को बदलने में आई समस्या पर भाषाई राजनीति शुरू हो गयी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम। के। स्टालिन और अन्य नेताओं न्न कथित तौर पर हिंदी थोपने के प्रयास के लिए एलआईसी की कड़ी आलोचना की। हालाँकि एलआईसी ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर ''भाषा पृष्ठ को बदलने में आई समस्या के लिए तकनीकी खामी को जिम्मेदार ठहराया है।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी ने बताया कि उसकी ''कॉर्पोरेट वेबसाइट कुछ तकनीकी समस्या के कारण भाषा पृष्ठ को परिवर्तित नहीं कर पा रही थी। एलआईसी इंडिया अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स जारी पोस्ट में कहा, ''समस्या का समाधान कर लिया गया है और वेबसाइट अंग्रेजी/हिंदी भाषा में उपलब्ध है। असुविधा के लिए हमें बेहद खेद है - टीम एलआईसी।

इससे पहले दिन में बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी को अपने होम पेज को केवल हिंदी में शुरू करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इससे ग्राहकों के लिए उस भाषा को न जानने के कारण वेबसाइट का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम। के। स्टालिन ने एलआईसी की वेबसाइट पर हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को हिंदी थोपने के लिए एक प्रचार उपकरण बना दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर एलआईसी के हिंदी वेबपेज का 'स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, ''एलआईसी की वेबसाइट हिंदी थोपने के लिए प्रचार का साधन बनकर रह गई है। यहां तक कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में प्रदर्शित किया गया है!

उन्होंने दावा किया कि यह कुछ और नहीं बल्कि जबरन संस्कृति और भाषा को थोपना और भारत की विविधता को कुचलना है। स्टालिन ने 'हैशटैग हिंदी थोपना बंद करो के साथ पोस्ट किया, ''एलआईसी की स्थापना सभी भारतीयों की सहायता के लिए की गई थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने अधिकांश अंशदाताओं को धोखा दे? हम इस भाषाई अत्याचार को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक डॉ। एस रामदास ने इस कदम को अन्य भाषा-भाषी लोगों पर हिंदी को 'स्पष्ट रूप से थोपना करार दिया। उन्होंने कहा कि एलआईसी का यह प्रयास अत्यधिक निंदनीय है क्योंकि यह गैर-हिंदी भाषी लोगों के बीच एक भाषा को 'थोपने का प्रयास है।

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ईके। पलानीस्वामी ने एलआईसी की वेबसाइट को पूरी तरह हिंदी में करने की आलोचना की और कहा कि संशोधित वेबसाइट फिलहाल उन लोगों के लिए अनुपयोगी है जो उस भाषा को नहीं जानते।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के। सेल्वापेरुन्थगई ने इस मुद्दे पर केंद्र की कड़ी आलोचना करते हुए उससे गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी भाषा थोपने की सभी गतिविधियों को तुरंत बंद करने को कहा।

मंच पर जगह न मिलने से भाजपा विधायकों ने जताई नाराजगी

आगरा (ईएमएस)। आगरा में आयोजित पंचायत राज सम्मेलन में भाजपा के दो विधायक मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने कार्यक्रम के बहिष्कार तक करने की धमकी दे डाली। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विधायक चौधरी बाबूलाल और विधायक छोटेलाल वर्मा आयोजक पर नाराज हो रहे हैं। तीसरे विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल दोनों विधायकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक बाबूलाल और छोटेलाल वर्मा कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है? छोटेलाल वर्मा कहते हैं कि हम पांच बार के विधायक हैं और तीन बार, एक बार के विधायक ऊपर बैठेंगे। साथ ही विधायक छोटेलाल कह रहे हैं कि सरकार में सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। विधायक चौधरी बाबूलाल मंच पर बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से कह रहे हैं कि क्या हम विधायक नहीं हैं, हमें बताइए मंत्रीजी। वीडियो में एसपी सिंह बघेल की आवाज सुनाई दे रही है और वह कहते हैं कि मैं समस्या का समाधान करूंगा। वहीं, विधायक चौधरी बाबूलाल कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पंचायत राज विभाग ने फतेहाबाद रोड स्थित ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को पंचायत सम्मेलन आयोजित किया था। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए थे। सम्मेलन में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया और विधायक रानी पक्षालिका सिंह को मंच पर जगह दी गई थी। विधायक छोटेलाल वर्मा, विधायक चौधरी बाबूलाल और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को मंच पर जगह नहीं दी गई। इस पर दोनों विधायक बाबूलाल और छोटेलाल वर्मा काफी नाराज हुए।

आयोजकों को विधायकों ने सुनाई खरी-खोटी

कार्यक्रम के बीच में ही दोनों विधायकों ने आयोजकों को खूब खरी-खोटी सुनाई। बाबूलाल ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात तक कह दी। मामला बढ़ता देख विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने दोनों विधायकों को शांत कराया। घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के दो विधायकों के मंच पर स्थान न मिलने के विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई बड़ा मसला नहीं था, बल्कि समस्या केवल मंच की जगह की थी। उन्होंने बताया कि आयोजन में 35 से ज्यादा विधायकों को निमंत्रण दिया गया था, जबकि मंच छोटा था। इस वजह से विधायकों को नीचे सोफे पर बैठने की व्यवस्था की गई थी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में तीन घंटे चली सुनवाई

नई ब्रेंच ने दोनों पक्षों की बातें सुनीं

प्रयागराज (ईएमएस)। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक सुनवाई चली। बता दें कि अहम मामला होने के चलते अब यह हाईकोर्ट की नई ब्रेंच को चला गया है। मंगलवार की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनीं। इस केस की सुनवाई के लिए जस्टिस न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र को नामित किया गया था। अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इस केस की सुनवाई इससे पहले न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे थे, जिनके सेवा अवकाश के कारण नई एकल पीठ गठित की गई है। अब नई ब्रेंच ने सुनवाई शुरू की है। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी थी। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया था। अब कोर्ट सभी 15 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 15 मामलों को एक साथ सुनवाई करने का फैसला दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अलग-अलग सुनने के लिए अर्जी लगाई थी।

देवबंद में 1993 में हुए विस्फोट का मुख्य आरोपी जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से गिरफ्तार

श्रीनगर/सहारनपुर (ईएमएस)। उत्तरप्रदेश पुलिस ने राज्य के देवबंद में 1993 में हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी नजीर अहमद वानी को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि वानी को उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। वानी ने हाल में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बडगाम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गया।

वानी (51) ने चुनावी हलफनामे में अपना व्यवसाय व्यापार बताया था। उसने अपने चुनावी हलफनामे में हालांकि देवबंद विस्फोट मामले का जिक्र नहीं किया है। उधर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और देवबंद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देवबंद में हुए बम धमाकों के आरोपी को जम्मू कश्मीर से रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि वह पिछले 31 वर्ष से सबको चकमा देकर अपना नाम और वेशभूषा बदलकर अलग-अलग जगह रह रहा था। जैन ने बताया कि वर्ष 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने के बाद पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे और उस दौरान देवबंद में भी कई स्थानों पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के दौरान अगस्त 1993 में शहर में पुलिसकर्मियों पर बमों से हमला किया गया था।

उन्होंने बताया कि उस समय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नजीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया था और 1994 में उसे न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

जन हितैषी

भारत के 90 फ़ीसदी परिवारों की आय 8334 रूपये, प्रति व्यक्ति आय 1136 रूपये

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार हर मंच से बड़े-बड़े दावे कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगले कुछ वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन जो वास्तविक स्थिति सामने आ रही है, वह काफी भयानक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1136 रुपए औसत है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत निम्न मिडल इनकम समूह में है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 12 साल तक भारत इसी समूह में बना रहेगा। लोअर और मिडल इनकम ग्रुप में 2036 तक भारत में वर्तमान नीतियों के अनुसार कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से दुनिया के देशों में भारत का नंबर 136वां है। 2022-23 की रिपोर्ट में भारत में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत के ऊपर कर्ज भी प्रति व्यक्ति लगातार बढ़ रहा है। अर्थात कर्ज लेकर लोगों को खर्च करना पड़ रहा है। भारत की एक फ़ीसदी आबादी की कमाई 53 लाख रुपए प्रति वर्ष है। भारत की सकल कमाई पर इस वर्ग का 22.6 फ़ीसदी हिस्सा है। इसके बाद 10 फ़ीसदी आबादी के हिस्से में 13.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आते हैं। भारत की कुल आमदनी का 57.7 फ़ीसदी हिस्सा 10 फ़ीसदी लोगों के पास पहुंच रहा है। भारत की कुल आबादी की 90 फ़ीसदी जनसंख्या अभी भी अपने जीवन-यापन के लिए कठिन संघर्ष कर रही है। 90 फ़ीसदी आबादी में से 40 फ़ीसदी आबादी की आय मात्र 1.65 लाख रुपया प्रतिवर्ष है। शेष 50 फ़ीसदी की आमदनी 71163 रुपए प्रति वर्ष है। जिसके कारण उनके परिवार का जीवन-यापन बड़ा मुश्किल हो रहा है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बाद भी बढ़ी हुई आय का हिस्सा मध्यम और गरीब वर्ग के पास नहीं पहुंच रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ग्रोथ मात्र एक फ़ीसदी लोगों की है। जो उच्चतम शिखर पर बैठे हुए हैं। यह एक फ़ीसदी लोग भारत में निवेश भी नहीं कर रहे हैं। ये कमाई का अधिकांश हिस्सा विदेशों में ले जाकर निवेश कर रहे हैं। जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय का औसत घटता जा रहा है। 2018 में दिल्ली का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। दिल्ली की प्रति व्यक्ति औसत आय देश में सबसे ज्यादा है। इस सर्वेक्षण में भी 90 फ़ीसदी परिवारों की आय 25000 रूपये प्रति मासिक से कम थी। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली संस्था कौशांबी रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर अरुण कुमार का मानना है। भारत में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत के 98 फ़ीसदी परिवार की औसत आय मात्र 16667 रुपए रह गई है। एक परिवार में चार से पांच व्यक्तियों का औसत माना जाए, तो प्रत्येक भारतीय की अधिकतम खर्च करने की सीमा मात्र 1894 प्रतिमाह रह गई है। मध्य और गरीब वर्ग की आय नहीं बढ़ रही है। वहीं उसके खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के जो मानक निर्धारित किए हैं। उसके अनुसार भारत की 90 फ़ीसदी आबादी गरीब श्रेणी में आती है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। भारत के 80 फ़ीसदी परिवारों को मुफ्त अनाज सरकार को देना पड़ रहा है। भारत और दुनिया के अर्थ विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह की भारत में नीतियां हैं, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का लाभ 90 फ़ीसदी आबादी के जीवन स्तर के सुधार में देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण भारत की आबादी है। भारत की आबादी के कारण अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। भारत कर्ज लेकर खर्च कर रहा है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई दिख रही है। दुनिया के देशों में अभी भी भारत का आय और खर्च के हिसाब से सूची में 136 वें नंबर पर स्थान है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है। उसकी वास्तविक स्थिति विश्व बैंक की रिपोर्ट उजागर कर रही है। शायद यही कारण है, दुनिया भर के निवेशक भारत के शेयर बाजार को अलविदा कहकर यहां से बाहर निकल रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार अगले 12 वर्षो तक लगभग यही स्थिति भारत की बनी रहेगी। गरीब और मध्यम वर्ग की आय और खर्च सीमित होकर रह गया है। भारत में कर्ज के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। आय और खर्च का संतुलन भारत में बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। जिसका असर अब अर्थव्यवस्था में पड़ना शुरू हो गया है। विश्व बैंक द्वारा इस स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था एवं विकास को लेकर बड़ी-बड़ी बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन धरातल में वास्तविक स्थिति 2014 से ज्यादा खराब दिखने लगी है। यही भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक सत्य है।

बच्चों के अधिकारों का हो सम्मान

दुनिया के कोने-कोने में मनाया जाता है बाल दिवस

(अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस (20 नवम्बर) पर विशेष)

बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस 'प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक अधिकार' विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1954 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस' मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जेनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्तूबर 1953 में मनाया गया था। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वी के कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में।

दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। आइए, देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है। जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास में, 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह में, 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को चीनी ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलीस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्की, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाइजीरिया, मई के आखरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में, 1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरा रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्तूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्तूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्तूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्तूबर को ईरान, 12 अक्तूबर को ब्राजील, अक्तूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्तूबर का चौथा रविवार को आस्ट्रेलिया, नवम्बर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवम्बर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है।

बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं। मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके और बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।(लेखक- योगेश कुमार गोयल/ईएमएस) (लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वोट जिहाद के लिए आज कत्ल की रात

झारखण्ड और महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव पहली बार सबसे अलग है । इन चुनावों में वोट के लिए जिहाद हो रहा है । जिहाद नहीं समझते ? यानि धर्मयुद्ध। महाराष्ट्र और झारखण्ड जीतने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा तमाम क्षेत्रीय दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए नैतिकता की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। इन दोनों राज्यों में 20 नवंबर को मतदान होना है इसलिए आज की रात सभी राजनीतिक दलों के लिए कत्ल की रात है।

जिहाद इस्लामी संस्कृति का प्रचलित शब्द था,है ,लेकिन इसे भाजपा ने पहले प्रेम विवाहों के संदर्भ में लव जिहाद बनाया और अब इसका इस्तेमाल सियासत में वोट जिहाद के रूप में किया जा रहा है । ये दोनों ही नारे हालाँकि हैं अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ किन्तु अब इनका इस्तेमाल सभी लोग कर रहे है। चुनाव को किसी धर्मयुद्ध की तरह लड़ने के लिए सारी बिसातें भाजपा की बिछाई हुई हैं। इन चुनावों में न स्थानीय मुद्दे हैं और न प्रचार अभियान में स्थानीय नेता। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने परप्रदेशी नेताओं की फ़ौज उतार दी है जो ध्रुवीकरण के लिए अपनी सारी प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं।

पिछले महीने हरियाणा और जम्मू-काश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद अचानक से महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव महत्वपूर्ण बन गए ,या कहिये बना दिए गए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के अलावा मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का इस्तेमाल दोनों राज्यों में झूठ परोसने,मतदाताओं के बीच उत्तेजना पैदा करने के लिए किया गया। विपक्ष की और से ले-देकर राहुल गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही चुनाव प्रचार में मोर्चा लेते दिखाई दिए। आईएमडीआईए गठबंधन के तमाम बड़े नेता या तो इन दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किये गए और न वे आये।

दोनों राज्यों वो मतदाताओं,प्रत्याशियों को आतंकित करने के लिए जब नारे काम न आये तो ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय तक ने खुलकर भाजपा के लिए काम किया। भाजपा के लिए दुर्भाग्य ये रहा कि चुनाव के अंतिम चरण में जहा एक बार फिर मणिपुर धधका वहीं प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्रचार छोड़कर नाइजीरिया और ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए जाना पड़ा । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को मणिपुर की हिंसा ने मैदान छोड़ने के लिए विवश कर दिया ,लेकिन योगी,सरमा और चौहान मोर्चे पर डटे हुए हैं। भाजपा ने लगता है कि इन दोनों राज्यों को जीतने के लिए हरियाणा की तरह इंतजाम कर लिया है। लेकिन मशीन और मशीनरी पर कितना भरोसा किया जा सकता है। कभी-कभी नेता ही नहीं मशीने भी बगावत कर जाती है।

इन दोनों राज्यों को जीतने से केंद्र की बैशखियों पर टिकी भाजपा गठबंधन की सरकार की ताकत में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हो सकती है । यदि 23 नवमबर को चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आये तो भाजपा को 25 नवमबर से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में लंबित विधेयकों को पारित करने में आसानी हो सकती है और यदि भाजपा ने ये चुनाव न जीते तो उसकी मुसीबतें संसद और संसद के बाहर बढ़ सकती है। इन दो राज्यों के चुनाव में यदि विपक्ष जीतता है तो विपक्ष को एक नयी संजीवनी मिल सकती है। महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव सत्ता और विपक्ष के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभा के चुनावों को लेकर पहली बार आम आदमी पार्टी परिदृश्य से बाहर दिखाई दे रही है किन्तु औबेदुल्ला औवेसी मैदान में मौजूद हैं। वे अपनी पार्टी के फायदे के लिए मौजूद हैं या भाजपा की मदद के लिए ये कहना कठिन है। इस चुनाव में बटने और न बंटने के बीच संघर्ष है। जो एक रहेगा ,वो सेफ रहेगा। जो बंटेगा वो कटेगा। कत्ल की रात में दोनों पक्षों की और से वोट जिहाद के लिए जी-तोड़ परिश्रम किया जा रहा है पहली बार केंचुआ ने भी इन चुनावों में बहुत सक्रियता दिखाई है । सभी दलों के नेताओं के उड़नखटोलों के साथ ही वाहनों की भी जमकर जांच की है। इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव इसलिए भी याद किये जायेंगे क्योंकि इन चुनावों में मुद्दों से ज्यादा मुर्दे काम आये हैं। काले खां घाटे में रहे लेकिन बिरसा मुंडा को फायदा हो गया।(लेखक-राकेश अचल/ईएमएस)

बुलडोज़र कार्रवाई न्याय नहीं नफ़रत व कुंठा की पराकाष्ठा

भारतीय राजनीति का स्वरूप अब बदल चुका है। अब हाथ जोड़कर विनम्रता प्रदर्शित करते नेताओं का युग शायद चला गया। कम से कम आज के दौर के नेताओं के तेवर उनके मुंह से निकलने वाले ज़हरीले शब्द बाणों, उनकी नीयत व कार्यशैली आदि को देखकर तो यही लगता है। ख़ासतौर पर गत एक दशक से जब से दक्षिणपंथी शक्तियों के हाथों में देश की सत्ता आई है तब से केंद्र व अनेक राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे फ़ैसले लिये गये जिनके कारण देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय तर्ज़-ए-सियासत की ख़ूब आलोचना हुई। भारतीय जनता पार्टी शासित विभिन्न राज्य सरकारों का ऐसा ही एक मनमाना व अमानवीय निर्णय था बुलडोज़र न्याय । हालांकि देश की विभिन्न अदालतों द्वारा पहले भी इस विषय पर संज्ञान लिया जा चुका है। परन्तु पिछले दिनों देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में नये व सख़्त दिशा-निर्देश के जारी किये और कहा कि उसका यह आदेश हर राज्य में भेजा जाए और सारे अधिकारियों को इसके बारे में बताया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की दो जजों की पीठ ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को केवल इसलिए तोड़ना कि वह अपराधी है या उन पर अपराध के आरोप हैं, क़ानून के ख़िलाफ़ है। न्यायालय ने कहा कि घर या कोई जायदाद तोड़ने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा। अगर किसी राज्य के क़ानून में इससे लंबे नोटिस का प्रावधान हो तो उसका पालन करना होगा। यह नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से देना होगा। इसके साथ ही कथित ग़ैर क़ानूनी ढांचे पर भी इस नोटिस को चिपकाना होगा। नोटिस पर पहले की तारीख़ न दी जाए। इसके लिए नोटिस की एक कॉपी कलेक्टर/ ज़िला मजिस्ट्रेट को भी ईमेल पर भेजनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि नोटिस में ये भी लिखना होगा कि कौन से क़ानून का उल्लंघन हुआ है,इस मामले में सुनवाई कब होगी। और जब सुनवाई हो तो उसका पूरा विवरण भी रिकॉर्ड करना होगा। न्यायालय के दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि सुनवाई करने के बाद अधिकारियों को अपने आदेश में वजह भी बतानी होगी। इसमें ये भी देखना होगा कि किसी संपत्ति का एक हिस्सा ग़ैर क़ानूनी है या पूरी संपत्ति ही ग़ैर क़ानूनी है। न्यायालय के अनुसार यदि तोड़-फोड़ की जगह, जुर्माना या और कोई दंड दिया जा सकता है तो वह दिया जाएगा। और यदि क़ानून में संपत्ति तोड़ने या गिराने के आदेश के ख़िलाफ़ कोर्ट में अपील करने का प्रावधान है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश के मुताबिक़ अगर ऐसा प्रावधान नहीं भी है, तो आदेश आने के बाद संपत्ति के मालिक/मालकिन को 15 दिन का समय मिलेगा ताकि वे स्वयं ही ग़ैर क़ानूनी ढाँचे को सही कर लें। यदि ऐसा नहीं हो, तब ही इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा सकती है। बुलडोज़र न्याय को लेकर आये सर्वोच्च न्यायालय के इन राहत भरे निर्देशों के बाद अब यह माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण फ़ैसले से बुलडोज़र से की जा रही विध्वंस की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों पर अब रोक लगेगी।

ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,राजस्थान,असम,हरियाणा जैसे अनेक भाजपा शासित राज्यों में गत एक दशक के दौरान सैकड़ों घरों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बुलडोज़र न्याय के नाम पर ज़मींदोज़ किया जा चुका है। सरकारें व प्रशासन ख़ुद ही न्यायलय की भूमिका अदा करता रहा है। किसी के मकान को इसलिये ध्वस्त कर दिया गया कि वह किसी आरोपी का मकान है। तो किसी मकान या भवन को इसलिये गिरा दिया गया कि वह अनधिकृत निर्माण है,उसके पास नक़्शा व निर्माण की अनुमति नहीं है,आदि। दरअसल इस तरह की कार्रवाई से पहले मौजूदा सत्ताधीश के तेवर व उनके शब्दों पर यदि ग़ौर करें तो स्वयं ही साफ़ हो जाता है कि सरकार व प्रशासन द्वारा बुलडोज़र कार्रवाई कोई न्याय की मिसाल क़ायम करने के लिये नहीं की जाती थी। बल्कि इसके पीछे साम्प्रदायिक व जातिवादी कुंठा काम कर रही थी। यही वजह है कि पूरे देश में अब तक जितनी भी बुलडोज़र कार्रवाइयां हुई हैं उनमें सबसे अधिक भवनों का ध्वस्तीकरण एक ही समुदाय के लोगों का ही हुआ है। हद तो यह है कि मध्य प्रदेश में एक घटना तो ऐसी भी हुई कि एक आरोपी किसी किराये के मकान में रहता था। परन्तु इस कुंठाग्रस्त सरकार व प्रशासन ने नफ़रत की आग में जलते हुये उस मकान को भी ध्वस्त कर दिया।

जहाँ तक अवैध निर्माण बताकर किसी भवन को गिराने का विषय है तो इस सम्बन्ध में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा में उठाये गये इस सवाल की भी अनदेखी नहीं की जा सकती जिसमें वे कई बार पूछ चुके हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री निवास का नक़्शा पारित है ? यदि है तो कहाँ है,किसके पास है,किसने देखा है ? अखिलेश के कहने का मतलब साफ़ है कि जिस भवन में बैठकर लोगों के भवन अवैध बताकर गिरवाये जा रहे हैं वही भवन अवैध रूप से निर्मित है। परन्तु दरअसल बुलडोज़र न्याय के पीछे मक़सद न्याय का हरगिज़ नहीं बल्कि यह कार्रवाई सत्ताधीशों के मुंह से समय समय पर निकलने वाले उनके शब्द बाणों को ही अमल में लाने का एक तरीक़ा है। अन्यथा आज तक इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने हम मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे,गर्मी उतार देंगे,बक्कल उतार देंगे,बंटेंगे तो कटेंगे जैसे निम्नस्तरीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया।

अब जबकि अदालत स्वयं यह कह चुकी है कि - किसी भी सभ्य समाज में बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ़ नहीं होना चाहिए, ऐसे में सत्ताधीशों को भी सोचना पड़ेगा कि वे भी स्वयं को एक सभ्य समाज के सभ्य नेता के रूप में पेश करें। धर्म जाति के अनुसार या इसके मद्देनज़र पक्षपात पूर्ण या विद्वेषपूर्ण फ़ैसले लेना निष्चित रूप से किसी सभ्य समाज के सभ्य नेता की पहचान हरगिज़ नहीं। सर्वोच्च न्यायायलय के फ़ैसले से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि बुलडोज़र कार्रवाई न्याय के लिये नहीं बल्कि यह नफ़रत व कुंठा की पराकाष्ठा है।(लेखक - तनवीर जाफ़री/ईएमएस)

अमरीका में शरण मांगने वालों में 855 फीसदी की वृद्धी

लाखों लोग छोड़ रहे हैं भारतीय नागरिकता ?

एक समय था जब ब्रिगेडियर उस्मान को बंटवारे के समय पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया था कि भारत मेरा देश है इस धरती में मेरे बुजुर्ग दफन हैंउन्होंने पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बनने की बजाय भारत का ब्रिगेडियर बना रहना स्वीकार किया और अपना नौसेरा बचाने के लिये शहीद हो गयेवह तो अनिश्चितता का समय था,जान-माल का खतरा था किंतु आज तो निश्चंतता का समय है। संवैधानिक और नियामक संस्थायें देश को आजादी के प्रति सजग कर रहीं हैं ऐसे दौर में कुछ खबरें हैरान भी करतीं हैं और चिंतित भी।

संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि पिछले 10 सालों में लगभग 15 लाख भारतीय नागरिकों ने देश की नागरिकता त्याग दी है इससे भी जो ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा है वह यह कि अमेरिका में शरण मांगने वाले भारतीयों की संख्या में 855 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विदित हो कि अमेरिका में शरण मांगने वाले दो तरह से शरण के लिए आवेदन करते हैं एक तो वह जिन्हें एफर्मेटिव कहा जाता है और दूसरा वे जिन्हें डिफेंसिव कहा जाता है यानि सुरक्षा की दृष्टि से वे अमेरिका में शरण की गुहार लगाते हैं अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की इमीग्रेंट एनुअल फ्लो रिपोर्ट बताती है कि 2023 में अमेरिका में शरण चाहने वाले आवेदकों में 41हजार 330 भारतीय शामिल थे जो कि 2022 की तुलना में 855 फ़ीसदी ज़्यादा है और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें से आधे आवेदक गुजरात राज्य के हैंजहां 2014 के बाद समृद्धि का विस्फोट हुआ है। समझना जरूरी है कि उन भारतीयों ने क्योंकर सुरक्षा एसाईलम के लिये आवेदन किया है? वर्ष 2022 में शरणार्थी के रूप में आवेदन करने वाले 14 हजार 570 भारतीयों में से 9200 ने डिफेंसिव एसाईलम यानि सुरक्षा शरण का आवेदन किया है।

भारत की अर्थव्यवस्था के उछालें भरने के दावे ,आम नागरिक के लिये सुरक्षा की गारंटी और बेहतर अवसरों के प्रचार के बीच भी अगर 41हजार 330 नागरिक अमरीका में शरण मांग रहे हैं और उनमें भी 50% से अधिक सुरक्षा कारणों से तो यह पड़ताल का विषय होना ही चाहिए ? इन सुरक्षा शरण चाहने वाले भारतीयों को देश में क्या खतरा लग सकता है? उनमें से आधे उस राज्य से क्यों हैं जिसमें सर्वाधिक विकास के दावे किये जा रहे हैं?

अमरीका में एलपीआर रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 लाख भारत में जन्मना नागरिक रहते हैं जो मेक्सिको में पैदा हुए अमरीकी नागरिकों के बाद सर्वाधिक संख्या है।अकेले 2022 में ही 1लाख 28 हजार 878 मेक्सीकन,65 हजार.960 भारतीय,53 हजार 413 फिलिपाईन नागरिकों को अमरीकी नागरिकता के लिये न्यूट्रिलाईज किया गया है।

ऐसा माना जाता है कि सामान्यतःआर्थिक ,शैक्षणिक अवसरों और राजनैतिक स्थिरता को देखते हुए सुरक्षित भविष्य की तलाश में लोग अपनी नागरिकता त्याग करने का कठिन फैसला लेते हैंअमरीका में रहने वाले 28 लाख 31 हजार 330 भारतीयों में 42 फीसदी भारतीय , अमरीकन नागरिकता के लिये अपात्र हैं। इसके बावजूद भारतीय ब्रेन इतनी बड़ी तादाद में जोखिम क्यों उठा रहा है?

मोटा-मोटी सभी देशों से आर्थिक प्रवासी अवसरों की तलाश करते हैं जिसमें आऊटफ्लो और इनफ्लो की मात्रा देश की वास्तविक परिस्थितियों का बखान कर देती है।

जिन 10 वर्षों में 15 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ने का आवेदन किया है उसी दौरान विगत पांच सालों में मात्र 5 हजार220 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है उनमें 4 हजार 552 यानि 87 फीसदी तो पाकिस्तानी, 8 फीसदी अफगानिस्तानी और 2 फीसदी बंगलादेशी हैं। इसका अर्थ है कि भारतीय नागरिकता त्यागने वालों के मुकाबले भारतीय नागरिकता चाहने वालों की संख्या 1 प्रतिशत भी नहीं है।

लंदन की हेनली एंड पार्टनर की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 हजार सुपर रिच धनाढय भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैंसरकार ने राज्यसभा में बताया है कि वह इन लोगों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि के बारे में अनभिज्ञ है।भारतीय टेक्स कानूनों,स्वास्थ्य सुविधाओं और इनवेस्टमेंट माईग्रेशन नागरिकता त्यागने की नयी बजह के रूप में सामने आ रही है। मेहुल चौकसी जैसे लोग इसी इवेस्टमेंट माईग्रेशन के नाम पर भाग खड़े हुए हैं।

नागरिकता छोड़ने का एक कारण यह भी है कि कई देश दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं करते,दूसरा बड़ा कारण अन्य देशों में निर्वाध आवाजाही के लिये भारतीय पासपोर्ट पर केवल 60 देशों में बीजा फ्री या आगमन पर बीजा सुविधा उपलब्ध है जबकि अमरीकन पासपोर्ट पर 186 देशों में यह सुविधा प्राप्त है। जन्म से भारतीय विदेशी नागरिकों को भारत में ओसीआई(ओवरसीज सिटीजन आफ इंडिया के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है) माना जाता हैगृह मंत्रालय ने सदन को जानकारी दी है कि आज ओसीआई की संख्या 1लाख 90 हजार है जो 2005 में मात्र 300 हुआ करती थीइसका अर्थ है कि लगभग 8 फीसदी नागरिकता त्यागने वाले भारतीय ही ओसीआई के रूप में देश से जुड़े रहना चाहते हैं।

अवसरों की तलाश और बेहतर जीवन की महत्वाकांक्षा मानव स्वभाव है किंतु जब अवसर देश से बड़ा बनने लगे तो मानिये चिंता का समय आ गया है। (लेखक-भूपेन्द्र गुप्ता/ईएमएस)(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

शब्द पहेली - 8193

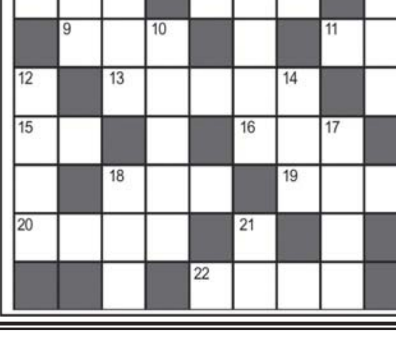

बाएँ से दाएँ

1. ईश्वरीय कृपा-4
4. कुंए पर पानी भरने का चबूतरा-4
6. दुर्बल का विलोम-3
8. सुनसान, नीरव-3
9. प्रेम प्रतिद्वंदी (उर्दू-3)
11. घोषवाक्य-2
13. चित्रपट, मायानगरी -3,2
15. सूर्य, भास्कर-2
16. उपनदी, कैनाल-3
18. व्यंग, परिहास-3
19. कौर, ग्रास-3
20. दफन करना-4
22. भूल, असावधानी-4

ऊपर से नीचे

1. अगुवा, रास्ता दिखाने वाला-4
2. सरुर, नशा, गरुर-2
3. चिंतन, विचारना-3
4. परजन भावना, गैरपन-5
5. भिड़ना, मुठभेड़-4
7. रेखा, लाईन-3
10. झाग बनना-5
12. सीमा, हद, बॉर्डर-4
14. शाखा, डाली-3
17. रिवाज, परंपरा-4
18. पाबंदी, रोक-3
21. स्वच्छ-2

शब्द पहेली -8192 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल-समाचार

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम में हरलीन की वापसी , शेफाली बाहर

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) चयनसमिति ने अगले माह होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए महिला टीम घोषित कर दी है। 16 सदस्यीय टीम में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को शामिल नहीं किया गया है। शेफाली पिछले कुछ समय से रन नहीं बना पा रही हैं, ऐसे में उन्हें ब्रेक दिया गया है। वहीं हरलीन देयोल की टीम में वापसी हुई है। शेफाली ने इस साल छह मैचों में सिर्फ 108 रन बनाए और उनका सबसे अधिक स्कोर 33 रन रहा है। वहीं हरलीन को करीब एक साल बाद टीम में जगह मिली हैं। हरलीने ने अपना आखिरी मैच 30 दिसंबर को वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। हरलीन के अलावा रिचा घोष, मिन्नू मनी , टिटास साधू और प्रिया पूनिया की वापसी हुई है। वहीं टीम में उमा छेत्री, डी हेमलता, श्रेयांका पाटिल और सायली सतघारे को शामिल नहीं किया गया है। भारतीय टीम अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी।

दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार है :

पहला एकदिवसीय : 5 दिसंबर, ब्रिसबेन, दूसरा एकदिवसीय : 8 दिसंबर, ब्रिसबेन, तीसरा एकदिवसीय :11 दिसंबर, पर्थ

टीम इस प्रकार है : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रिया पूनिया, जेमिमा रौड्रिग्स, हरलीन देयोल, यास्तिका भाटिया, रिचा घोष, तेजल हसाबनिस, दीप्ति शर्मा, मिन्नू मनी, प्रिया मिश्रा, राधा यादव, टिटास साधू, अरूंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, साइमा ठाकोर।

पडिक्कल अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे, शमी अभी घरेलू क्रिकेट खेलेंगेः बीसीसीआई

पर्थ (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रुकेंगे और और भारतीय टीम के साथ ही बैकअप बल्लेबाज के तौर पर रहेंगे। इसका कारण है कि बल्लेबाज शुभमन गिल चोटिल होने के कारण पहले टेस्ट से बाहर हैं। पडिक्कल ने भारत ए की ओर से यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। बीसीसीआई टीम प्रबंधन ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से सलाह के बाद ही पडिक्कल को बैकअप के तौर पर रखा है। वहीं शुभमन गिल अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गए हैं जबकि कप्तान रोहित शर्मा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट से बाहर हैं। बल्लेबाज केएल राहुल के चोटिल होने की भी चिंता है, जिन्हें कोहनी में चोट लगी है। वहीं बीसीसीआई ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अभी ऑस्ट्रेलिया भेजने से इंकार करते हुए कहा कि अभी वह घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। बीसीसीआई नहीं चाहता है कि शमी जल्दबाजी में उतरकर कोई जोखिम लें।

जहां तक पडिक्कल की बात है। ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ अपनी चार पारियों में इस बल्लेबाज ने 36, 88, 26 और 1 के स्कोर दर्ज किए। हालांकि ये प्रदर्शन सामान्य परिस्थितियों में सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है पर टीम प्रबंधन का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई हलातों से उनका अनुभव और परिचितता उन्हें बल्लेबाजी बैकअप के रूप में बेहतर विकल्प बनाती है। पडिक्कल ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट खेला था।

चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर अभी तक आईसीसी से नहीं मिला कोई जवाब : पीसीबी

लाहौर (ईएमएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट के आयोजन को लेकर अड़ियल रुख बना हुआ है। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आने की बात नहीं कही है। नकवी ने कहा कि वह टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर आईसीसी से बात करते रहे है पर अभी तक आईसीसी ने उन्हें किसी अन्य जगह पर टूर्नामेंट के आयोजन की बात नहीं कही है। नकवी ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है, हमने पहले भी यह कहा है और हम उस रुख पर बने रहेंगे। वहीं बीसीसीआई ने इस महीने की शुरुआत में ही आईसीसी से कह दिया था कि वह अपनी टीम को पाक नहीं भेजेगा और उसके मैचों का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत ही किसी अन्य देश में किया जाये पर पीसीबी ने इस हाइब्रिड मॉडल को मानने से इंकार कर दिया था। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का यह आयोजन फरवरी-मार्च में होना है।

नकवी ने ये भी कहा था कि सुरक्षा सहित कोई मामला है तो वह बीसीसीआई हमसे करे। हम उस समस्या को दूर करेंगे। साथ ही कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने का कोई कारण है।.

पीसीबी प्रमुख ने कहा कि उसने बीसीसीआई द्वारा अपनी टीम नहीं भेजने के फैसले पर आईसीसी को एक पत्र भेजा है। हम उसी को लेकर आईसीसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं जिसे हम मामले में आगे बढ़ सकें।

नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। हम लाहौर, कराची और रावलपिंडी में तीनों स्टेडियमों का निर्माण और फिनिशिंग पूरा करने की अपनी समय सीमा से आगे हैं। मैं यहां निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में बात करने आया हूं और हम आईसीसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कार्यक्रम की घोषणा करनी है.

गौरतब है कि भारत और पाकिस्तान ने 2012 के बाद से आपस में कोई सीरीज नहीं खेली है पर वे आईसीसी टूर्नामेंटों में वे एक-दूसरे का सामना करते रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान द्वारा आयोजित एशिया कप को भी हाइब्रिड मॉडल में बदल दिया गया था, क्योंकि तब भी भारत ने पाक का दौरा करने से इंकार कर दिया था। माना जा रहा है कि इस बार भी अंत में पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाएगा।

शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बंगाल टीम में शामिल

कोलकाता (ईएमएस)। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रणजी ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए भी शामिल किया गया है। भारतीय टीम में वापसी के प्रयासों में लगे शमी का लक्ष्य अब इसमें भी बेहतर प्रदर्शन कर अपनी फिटनेस साबित करना रहेगा। शमी शनिवार से शुरू होने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल की ओर से खेलेंगे।

शमी को बंगाल टी20 टीम में शामिल करने का कारण उनकी फिटने को देखना है जिससे कि जरुरत पड़ने पर उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया जा सके। शमी टखने की चोट के कारण पिछले साल हुए एकदिवसीय विश्वकप के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर थे। इसी कारण उन्हें पहले घरेलू क्रिकेट में अपने को साबित करने कहा गया था। शमी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी मुकाबले में बंगाल की ओर से खेलते हुए सात विकेट लिए थे।

वहीं कहा जा रहा है कि उन्हें पहले टेस्ट के लिए इसलिए शामिल नहीं किय गया क्योंकि चयनकर्ता केवल एक रणजी ट्रॉफी मैच में फिटनेस के आधार पर उन्हें जल्दबाजी में टीम में शामिल नहीं करना चाहते। राष्ट्रीय चयनकर्ता चाहते हैं कि शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ और मैच खेलें। उनकी फिटनेस अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरुप पहुंच जाये।

टूर्नामेंट के लिए बंगाल टीम :

टीमः

सुदीप कुमार घरामी (कप्तान), अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुदीप चटर्जी, शाहबाज अहमद, करण लाल, रितिक चटर्जी, रित्विक रॉय चौधरी, शाकिर हबीब गांधी (विकेटकीपर), रणजोत सिंह खैरा, प्रयास रे बर्मन, अग्निव पान (विकेटकीपर), प्रदीप्ता प्रमाणिक, सक्षम चौधरी, मोहम्मद शमी, ईशान पोरेल, मोहम्मद कैफ, सूरज सिंधु जयसवाल, सायन घोष, कनिष्क सेठ और सौम्यदीप मंडल।

सीमिंग ऑलराउंडर के तौर पर नितीश को मिल सकता है अवसर

पर्थ (ईएमएस)। भारतीय टीम मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट की तैयारियों में लगी है। इसके लिए भारतीय टीम में युवा ऑलराउडर नितीश रेड्डी को अवसर मिल सकता है। टीम में इस समय दो अनुभवी आलराउंडर आर अश्विन और रवीन्द्र जडेजा है पर ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर मजबूती देने के लिए सीमिंग ऑलराउंडर के तौर पर नितीश को जगह मिल कसती है। पर्थ में चल रहे अभ्यास सत्र में टीम प्रबंधन सभी खिलाड़ियों पर गंभीरता से नजर रख रहा है पर नितीश से नई और पुरानी गेंद के साथ साथ जिस प्रकार से गेंदबाजी और इसके बाद नेट्स पर बल्लेबाजी करायी जा रहा है उससे साफ है कि नितीश को पहले टेस्ट के लिए अंतिम ग्यारह में जगह मिल सकती है। नितीश को नेट्स में रफ़्तार के साथ अच्छी उछाल मिल रही है और वह स्टीक गेंदबाज़ी भी करते नज़र आए जिससे टीम प्रबंधन प्रभावित है। इस प्रकार ये युवा क्रिकेटर अपनी गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी से ऑलराउंडर की जगह भर सकते हैं। .

नितीश ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले सीरीज टी20 में डेब्यू के बाद से ही काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। नीतीश ने अभी तक 23 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। उन्होंने इस दौरान 779 रन बनाए हैं। नीतीश ने इस दौरान एक शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। वे फर्स्ट क्लास मैचों में 56 विकेट भी ले चुके हैं। उनका एक मैच में 119 रन देकर 8 विकेट लेना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा लिस्ट ए के 22 मैचों में 403 रन बनाए हैं। वे इस फॉर्मेट में 14 विकेट ले चुके हैं।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीददारी हावी रहने से आया है। इस तेजी के साथ ही पिछले दिनों से जारी गिरावट पर भी अंकुश लग गया। आज कारोबार के दौरान इंडेक्स में दिग्गज कंपनियों एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में उछाल से बाजार ऊपर आया। इसके अलावा घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी से भी बाजार को बल मिला।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 0.31फीसदी तकरीबन 239.37 अंक बढ़कर 77,578.38 पर बंद हुआ। इसी तरह 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.28 फीसदी तकरीबन 64.70 अंक बढ़कर 23,472.75 पर बंद हुआ पर निफ्टी की 50 कंपनियों में से 27 के शेयर गिरावट पर बंद हुए।

आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सबसे ज्यादा 3.55 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। इसके साथ ही टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और इंफोसिस के शेयर भी बढ़े।

वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति, टाटा स्टील और भारती एयरटेल के शेयरों में गिरावट रही।

बाजार जानकारों के अनुसार आज निचले स्तरों पर हुई खरीदारी और दिग्गज कंपनियों के शेयरों एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और एमएंडएम में उछाल से बाजार ऊपर आया है। बाजार में और भी उछाल आता पर अंतिम घंटे में हुई गिरावट से उसकी तेजी कुछ हद तक कम हुई

वहीं विदेशी निवेशकों ने गत दिवस 1,403.40 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,330.56 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

वहीं एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग बढ़त पर बंद हुए जबकि यूरोपीय बाज़ार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार गत दिवस बढ़त पर बंद हुए।

वहीं इससे पहले बाजार मंगलवार को तेजी के साथ खुला। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनियां भर से मिले मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीदारी हावी रहने से हुआ है। सुबह कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 266 अंकों की बढ़त के साथ 77,605 पर कारोबार करता दिखा, जो 0.34 फीसदी की बढ़त दिखाता है जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 83.70 अंकों तकरीबन 0.36 फीसदी की तेजी के साथ 23,537 का स्तर पर पहुंच गया।

आज शेयर बाजार रहेगा बंद

नई दिल्ली,(ईएमएस)। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। इस वजह से शेयर बाजार बंद रहेगा। इस दौरान शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं होगी। शेयर बाजार में कब छुट्टी रहती है, इसे लेकर बीएसई और एनएसई साल का कैलेंडर जारी करते हैं। चूंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी दिन छुट्टी के बारे में कैलेंडर में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में बीएसई और एनएनई नोटिफिकेशन के जरिए छुट्टी की घोषणा करते हैं।

शेयर बाजार में इस हफ्ते भी तीन दिन छुट्टी रहेगी। पिछले हफ्ते भी तीन दिन छुट्टी थी। पिछले हफ्ते 15 नवंबर को गुरुनानक जयंती के मौके पर शेयर बाजार बंद था। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी हो गई थी।

इंडोनेशिया में आईफोन 16 पर बैंन.......हटवाने दिया 844 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव

मुंबई (ईएमएस)। इंडोनेशिया में एप्पल ने आईफोन 16 पर लगे बैन को हटवाने के लिए सरकार को 844 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक, एप्पल ने अपना निवेश प्रस्ताव करीब दस गुना बढ़ा दिया है। यह कदम इंडोनेशिया सरकार को आईफोन 16 पर बैन हटाने के लिए मनाने की नई कोशिश के रूप में सामने आया है। एप्पल अब दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगले दो साल में करीब 844 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल का पहले का निवेश प्रस्ताव केवल 10 मिलियन डॉलर (करीब 84 लाख रुपए) का था। लेकिन अब एप्ल ने अपनी निवेश राशि में भारी वृद्धि की है। इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय ने अभी प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है, हालांकि पिछले माह आईफोन 16 की बिक्री पर बैन लगा दिया गया था।

इंडोनेशिया सरकार ने बैन के बाद एप्पल से कहा था कि वहां अपने स्मार्टफोन के लिए रिसर्च और विकास पर ज्यादा ध्यान दे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी निवेश योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करे। मंत्रालय का कहना है कि एप्पल ने अपने पिछले निवेश के तहत डेवलपर अकादमियों के माध्यम से लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपिया (करीब 801 करोड़ रुपए) का निवेश किया था, जो कि उसकी घोषित प्रतिबद्धता से कम था। एप्पल के अधिकारियों को पहले इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री अगुस गुमीवांग कार्तसस्मिता से मिलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वे जकार्ता पहुंचे, तब उन्हें बताया गया कि मंत्री उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद उन्हें मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल से मिलना पड़ा। यह घटना एप्पल के निवेश प्रस्ताव और सरकार के साथ बातचीत में अहम मोड़ साबित हुई।

इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि एप्पपल की लोकल यूनिट ने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 40 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए आईफोन 16 की बिक्री को बैन कर दिया गया।

पीएम मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति ने की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा

रियो डी जेनेरियो(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता रियो डी-20 शिखर सम्मेलन में हुई। भारत-फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। 2047 तक भारत-फ्रांस के बीच संबंधों को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। जिसे होराइजन 2047 रोडमैप और अन्य द्विपक्षीय घोषणाओं को ध्यान में रख कर आकार दिया गया।

मैक्रों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्स पर लिखा- मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलना हमेशा ही बेहद खुशी की बात होती है। इस साल की शुरुआत में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक की सफल मेजबानी के लिए उन्हें बधाई दी। जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा और जून में इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी बैठक के बाद, दोनों नेताओं के बीच इस साल तीसरी बार मिले और बैठक की।

पीएम मोदी ने कहा कि मुलाकात में हमने चर्चा की कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे अन्य भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। हम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। दोनों नेताओं ने अपनी मित्रता और संबंधों को मजबूत किया है। मैक्रों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को भविष्य में निर्णायक भूमिका निभाने वाला एक दिग्गज बताया।

मैक्रों ने पीएम मोदी को गले लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- भारत के साथ हमारी साझेदारी समृद्ध और बहुआयामी है। पिछले जनवरी में मेरी राजकीय यात्रा के दौरान शुरू की गई पहलों की प्रगति के साथ-साथ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की भी समीक्षा की थी। विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग में हासिल की गई प्रगति की सराहना की।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने बहुपक्षवाद को फिर से जीवंत करने और सुधारने तथा एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गयी है। सुबह सोने चांदी के वायदा भाव में तेजी रही। सुबह सोने के वायदा भाव 75,400 रुपये के भाव पर खुला। चांदी के वायदा भाव 91,050 रुपये के करीब थे। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की वायदा कीमतों में तेजी आई।

सोने का वायदा बेंचमार्क दिसंबर अनुबंध एमसीएक्स पर आज 153 रुपये की तेजी के साथ 75,200 रुपये के भाव पर खुला। यह अनुबंध 355 रुपये की तेजी के साथ 75,402 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। एक समय ये 75,429 रुपये के भाव पर दिन के उच्च और 75,200 रुपये के भाव पर दिन के निचला स्तर पर पहुंचा। सोने के वायदा भाव इस साल 79,775 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे थे।

वहीं चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर अनुबंध आज 235 रुपये बढ़कर के 90,748 रुपये पर खुला। एक समय ये अनुबंध 552 रुपये की तेजी के साथ 91,065 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 91,100 रुपये के भाव पर दिन का उच्च और 90,748 रुपये के भाव पर दिन का निचला स्तर हासिल किया। इस साल चांदी के वायदा भाव 1,00081 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा

दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी के वायदा भाव में तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स में सोना 2,616.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,614.60 डॉलर प्रति औंस था। दसके अलावा कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 31.24 डॉलर के भाव पर खुले, इसका पिछला बंद भाव 31.22 डॉलर था।

वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पीएम मोदी ने की वकालत

रियो डी जेनेरियो(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 समिट के उद्घाटन भाषण में दुनिया के अमीर देशों को कामयाबी का मंत्र बताया। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि यह पिछले वर्ष था। नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जनहितैषी निर्णयों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया है। हमारी कामयाबी का एक ही मंत्र है कि हम बैक बेसिक्स और मार्च टू फ्यूचर वाला अप्रोच रखते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में तुरंत सुधार की नसीहत दी।पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के स्कीम के तहत 20 बिलियन डॉलर किसानों को दिया गया है।

पुतिन ने नई परमाणु नीति पर किए हस्ताक्षर, कहा- बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो होगा न्यूक्लियर हमला

बाइडन के फैसले से एटमी जंग के मुहाने पर दुनिया

मास्को(ईएमएस)। अमेरिका में जो बाइडन की सरकार ने जाते-जाते यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के भीतर हमले की मंजूरी दी है, उससे माहौल बिगड़ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक अहम फैसले के तहत संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नई नीति के तहत अगर कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो इसे देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा और उस स्थिति में रूस की सरकार परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। हालांकि इस स्थिति में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। पुतिन का यह फैसला रूस-यूक्रेन युद्ध के एक हजार दिन पूरे होने के अवसर पर सामने आया है।

अमेरिका में जो बाइडन की सरकार ने जाते-जाते यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के भीतर हमले की मंजूरी दे दी है। इस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही थी। पुतिन द्वारा संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर के कदम को भी बाइडन के फैसले का ही जवाब माना जा रहा है। रूस की नई परमाणु नीति में ये प्रावधान किया गया है कि रूस पर अगर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है तो उसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है।

नई नीति में किए गए हैं ये बदलाव

रूस की पूर्व की परमाणु नीति के तहत सिर्फ रूस या इसके सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की विश्वसनीय सूचना के बाद ही रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब नई नीति के तहत बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही, क्रूज मिसाइल, बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले या अन्य उड़ने वाले वाहनों के जरिए हमले की स्थिति में भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। खास बात ये है कि पुरानी नीति में रूस के सहयोगी बेलारूस पर हमले की स्थिति में भी रूस द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का प्रावधान था, लेकिन संशोधित नीति में ये प्रावधान हटा दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है। ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उसपर हमला न कर सकें। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। जिसके बाद पुतिन ने यह कदम उठाया है।

ईरान के सुप्रीमो अयातुल्लाह के कोमा में होने की अटकलें खारिज

तेहरान (ईएमएस)। ईरान के सुप्रीमो 85 वर्षीय अयातुल्लाह अली खामेनेई के कोमा में होने की खबर को खामेनेई के अधिकारिक कार्यालय ने झूठ करार दिया है। आधिकारिक कार्यालय ने उनकी एक तस्वीर साझा की। इसमें खामेनेई को लेबनान में ईरान के राजदूत मोजतबा अमानी के साथ बातचीत करते हुए देखा गया। खामेनेई के एक्स अकाउंट पर यह तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया, इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने लेबनान में ईरान के अनुभवी राजदूत मोजतबा अमानी से दोपहर अपने दैनिक बैठकों के दौरान मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई अक्टूबर में गंभीर रूप से बीमार थे और उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। वहीं, खामेनेई ने पांच अक्टूबर को पांच साल बाद पहली बार एक सार्वजनिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन और लेबनान के हमास और हिज्बुल्लाह के समर्थन में बयान दिया था। मोजतबा अमानी, जिनसे खामेनेई ने मुलाकात की, सितंबर में लेबनान में एक विस्फोट में घायल हो गए थे। यह विस्फोट हिज्बुल्लाह के उपकरणों में हुआ था, जिसमें 39 लोगों की मौत और लगभग 3,000 लोग घायल हुए थे। अमानी ने अपने सेहत से जुड़ी रिपोर्ट खामेनेई को सौंपी। पिछले महीने अपने भाषण में खामेनेई ने कहा था कि इजरायल जल्द ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने इजरायल पर मिसाइल हमलों को जनता की सेवा बताते हुए इसे जायज ठहराया।

जी-20 सम्मेलन में मिले मोदी-बाइडन, व्यापार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हुई बातचीत

रियो डी जेनेरियो, (ईएमएस)। ब्राजील में जी-20 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच यह मुलाकात अहम थी, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। यह मुलाकात भारत-अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

इससे पहले पीएम मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर बात की। उन्होंने बैठक में विकासशील देशों के लिए एकजुटता और सहयोग के महत्व को बताया। इस सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

मोदी ने गुटेरेस से भारत की भूमिका और सहयोग के विषय में भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में भारत के वैश्विक नेतृत्व और विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका पर जोर दिया।

एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान 8 जवानों की मौत, 9 आतंकी ढेर

इस्लामाबाद(ईएमएस)। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई जबकि 9 आतंकी भी मारे गए हैं। दरअसल, पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने सोमवार देर रात एंटी-टेरर ऑपरेशन चलाया।

इस दौरान हथियारबंद उग्रवादियों और पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 9 उग्रवादी मारे गए और 8 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत हो गई। इस स्पेशल ऑपरेशन को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अंजाम दिया गया. खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में कुछ देर चली मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-इस्लाम के 2 बड़े कमांडर भी मारे गए। इस ऑपरेशन में 7 उग्रवादी और 6 सिक्योरिटी पर्सनल घायल भी हुए हैं। ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला और इस दौरान करीब 3 इलाकों में पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात रहे। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि आस-पास के इलाकों के कुछ निवासी भी इस आपरेशन में घायल हो गए। बता दें कि जिस इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहां कई बार चीनी नागरिकों के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना के जवानों पर भी हमला हो चुका है।

किसी की लगी नजर.... बीते एक साल से निवेशकों को निराशा कर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर

नई दिल्ली (ईएमएस)। पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट में गिरावट जारी है। हालांकि मंगलवार को शेयर मार्केट में काफी दिनों बाद तेजी दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर देश की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ समय से निवेशकों को निराश कर रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर की कीमत पिछले एक साल काफी गिर गई है। मंगलवार को रिलायंस के शेयरों में एक फीसदी से ज्यादा की तेजी आई। यह तेजी काफी समय बाद दिखाई दी है। इसके बावजूद इसकी कीमत पिछले 11 माह के स्तर पर है।

पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। एक साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 1174.68 रुपये थी। अब इस शेयर की कीमत 1277.15 रुपये है। इसके बाद शेयर में एक साल में करीब 8.60 फीसदी की ही तेजी आई है। मंगलवार को इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव जारी था। निफ्टी 50 ने एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेहतर प्रदर्शन किया है। निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। निफ्टी 50 एक साल पहले 19694 अंक पर था। अभी यह करीब 23,747 पर है।

रिलायंस का शेयर इस साल जुलाई में 1608 रुपये पर पहुंच गया था। यह इसका अब तक का हाई है। लेकिन अपने हाई पर पहुंचने के बाद मानों मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर पर किसी की नजर लग गई। इसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया। इसके बाद जुलाई से लेकर अब तक इसमें 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं पिछले एक महीने में रिलायंस का शेयर करीब 6.80 फीसदी गिर गया है। वहीं पिछले 6 महीने में भी इसमें तगड़ी गिरावट आई है। इतने समय में यह 11 फीसदी से ज्यादा गिर गया है। गिरावट के बावजूद जानकार इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदकर रखा जा सकता है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है।

साल 2031 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली (ईएमएस)। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2031 तक 7 ट्रिलियन डॉलर के आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। इस ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान देश की जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि, वित्त वर्ष 2025 से लेकर 2031 तक की वार्षिक वृद्धि दर महामारी से पहले के दशक की औसत वृद्धि दर (6.6 प्रतिशत) के आसपास होगी। इस विकास को मुख्य रूप से पूंजीगत खर्च और उत्पादकता में सुधार से प्रेरित बताया गया है। 2023-24 के चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 6.8 प्रतिशत तक रहने की संभावना है, जिसका कारण उच्च ब्याज दरें और सख्त लेंडिंग नियम हैं, जिससे शहरी मांग पर असर पड़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयासों का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विकास पर देखने को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 2024-25 में औसत 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 5.4 प्रतिशत से कम होगी।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौसम की स्थिति और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं विकास और महंगाई के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हैं। इस वर्ष खरीफ की बुआई अधिक हुई है, लेकिन बेमौसम बारिश और अन्य मौसम संबंधित प्रभावों को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती हैं, व्यापार में विघ्न आ सकता है और तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो महंगाई और इनपुट लागत को प्रभावित कर सकती है।

यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देकर बाइडेन ने............ट्रंप और पुनित दोनों को साधने की कोशिश की

कीव (ईएमएस)। रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से चल रही जंग में अमेरिका ने नया कदम उठाया है। जो बाइडन प्रशासन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लांग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद यूक्रेन अब रूस के भीतर गहराई तक हमले कर सकता है। युद्ध में यह पहली बार हुआ है कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं, रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क पर नियंत्रण बनाए रखा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका का यह फैसला रणनीतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडन प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध खत्म कराने का श्रेय नहीं देना चाहता। इसके अलावा, अमेरिका कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन का कब्जा बरकरार रखकर रूस पर नैतिक दबाव बनाना चाहता है। इस दबाव के द्वारा अमेरिका भविष्य की बातचीत में जमीन के बदले जमीन की नीति पर जोर देगा।

वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यदि नाटो द्वारा यूक्रेन को दी गई लॉन्ग रेंज मिसाइलें रूस की जमीन पर इस्तेमाल होती हैं, तब इस परमाणु हमले के रूप में देखा जाएगा। रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को सक्रिय करने की बात भी कही है। अमेरिका द्वारा दी गई एटीएसीएमएस (आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम) जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती हैं। 300 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइलें रूस के लिए चुनौती हैं, लेकिन रूस के पास इन्हें जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। इस कदम के बाद युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है।

रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का उद्देश्य केवल सैन्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। दूसरी विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी विदेशी सेना ने रूसी जमीन पर कब्जा किया है। अमेरिका चाहता है कि कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन का कब्जा बरकरार रहे, तब ताकि बातचीत के दौरान तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि, रूस की ओर से संकेत स्पष्ट हैं कि जब तक वह अपने कब्जे की जमीन वापस नहीं पा लेता, तब तक बातचीत की संभावना नहीं है। यूक्रेन अब तक अमेरिकी और नाटो सहयोगियों की मदद से जंग लड़ता आ रहा है।

इमरान समर्थकों से डरी शहबाज सरकार, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू

इस्लामाबाद (ईएमएस)। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थकों को लेकर डरी हुई है। इमरान खान की पार्टी के समर्थकों के प्रदर्शन की योजना के मद्देनजर राजधानी और आसपास के क्षेत्र में पांच या इससे अधिक लोगों के जमा होने एवं सभी तरह की सभाओं पर दो महीने के लिए रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि एक साल से अधिक समय से जेल में बंद उसके संस्थापक इमरान खान को रिहा करने पर सरकार को बाध्य करने के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया जाएगा। संघीय सरकार ने इसके बाद इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी जिसके तहत लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। स्लामाबाद के जिला मजिस्ट्रेट उस्मान अशरफ के कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार धारा 144 लागू कर दी गई है क्योंकि समाज के कुछ तत्व गैरकानूनी तरीके से जमा होने की योजना बना रहे हैं जिससे सार्वजनिक शांति बाधित हो सकती है। अधिसूचना के तहत पांच या अधिक लोगों के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वे सार्वजनिक शांति और सौहार्द को खतरे में डाल सकते हैं, मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

ब्रैसवेल से पहले भी नशे में कई दिग्गजों ने बनाये हैं रिकार्ड

सोबर्स, गिब्स सहित कई दिग्गज हैं शामिल

मुम्बई (ईएमएस)। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डग ब्रैसवेल को इस साल की शुरुआत में एक टी20 मैच में आक्रामक गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जीत दिलायी और वह मैन ऑफ द मैच भी बने पर इसके बाद ब्रैसवेल डोप टेस्ट में पकड़े गए और दोषी पाए गए और उन्हें एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ये मैच सेंट्रल स्टैग्स और वेलिंगटन के बीच खेले खेला गया था और इसमें ब्रेसवेल पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का आरोप था। इस मैच में ब्रेसवेल ने 21 रन देकर 2 विकेट लिए थे और 11 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली थी। इसके बाद ब्रेसवेल पर एक महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी कमीशन ते काहू रौनुई ने इस तेज गेंदबाज पर ये प्रतिबंध लगाया था हालांकि यह भी पाया गया कि कोकीन का सेवन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले किया गया था और इसलिए इस तेज गेंदबाज को कम सजा मिली।

विश्व में कई ऐसे दिग्गज क्रिकेटर भी हुए हैं जिन्होंने शराब और ड्रग्स के नशे में खेलते हुए कई रिकार्ड बनाये हैं। ऐसे क्रिकेटरों की सूची काफी लंबी है और इसमें महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स तक शामिल रहे हैं। इसके अलावा नशे में खेलने वाले क्रिकेटरो में हर्शेल गिब्स, दिवंगत एंड्रयू सायमंड्स के अलावा दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स भी शामिल रहे हैं।

ब्रैसवेल को कोकीन के सेवन का दोषी पाया गया था। उन्हें इस गलती की सजा भी दी गई और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उन पर एक महीने का प्रतिबंध लगाया। ब्रैसवेल ने जनवरी में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और वेलिंगटन के बीच घरेलू टी20 मैच नशे में खेला था। मैच के बाद जांच में उन्हें पॉजिटिव पाया गया। ब्रैसवेल ने इस मैच में 2 विकेट झटके थे और 11 गेंद में 30 रन की पारी खेली थी। इसके चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।

सोबर्स महान ऑलराउंडर रहे हैं पर कई बार वे देर रात तक शराब पीते रहे और सुबह नशे में मैदान पर उतरे। उन्होंने कई शतक नशे में ही बनाए। गिब्स के नाम भी मैच फिक्सिंग से लेकर शराब पीकर खेलने जैसे कई मामले हैं। गिब्स ने अपनी आत्मकथा में स्वयं माना है किउन्होंने कई बार मैच से कुछ घंटे पहले शराब पी और फिर मैदान पर उतरे। गिब्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 रनों की पारी के लिए याद किया जाता है, जिसके बल पर दक्षिण अफ्रीका ने 435 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य प्राप्त किया था। गिब्स ने बाद में ये स्वीकार किया था कि उन्होंने 175 रन की यह पारी नशे में खेली थी।

ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत बल्लेबाज साइमंड्स को उनकी बेहतरीन क्रिकेट के साथ-साथ विवादों के लिए भी जाना जाता है। अपने ही बल पर मैच बदलने वाले साइमंड्स को अनुशासनहीनता के चलते कई बार टीम से बाहर भी किया गया था। उन्हें शराब की भी बुरी आदत थी। साइमंड्स ने कई बार माना कि वे रातभर पार्टी करने के बाद सुबह मैच खेलने उतरे थे।

चीन में बेरोजगारी के चलते हिंसक हो रहे युवा, कुछ दिनों में 43 की हत्या

बीजिंग (ईएमएस)। चीन में अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात के चलते युवा वर्ग में हताशा बढ़ती जा रही है। बीते कुछ सालों में चीन की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आवास क्षेत्र में गिरावट देखी गई है। इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ी है, बल्कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, जिससे वे मानसिक तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। चीन के आर्थिक संकट की वजह से वहां के युवा निराश हो गए हैं। नौकरी की कमी और आर्थिक कठिनाइयों के चलते कुछ युवाओं ने हिंसा तक की घटनाओं को अंजाम दिया। हाल ही में पूर्वी चीन में एक युवक ने अपनी नौकरी से परेशान होकर चाकू से हमला कर आठ लोगों की हत्या कर दी और 17 अन्य को घायल कर दिया। इसी तरह की एक दूसरी घटना में दक्षिणी चीन के झुहाई में एक व्यक्ति ने अपनी कार से एक भीड़ को रौंद दिया, जिससे 35 लोग मारे गए और 43 घायल हुए। अक्टूबर में शंघाई के सुपरमार्केट में चाकूबाजी की घटना भी इसी तरह की एक दुखद घटना थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं के पीछे मुख्य कारण युवाओं का मानसिक तनाव और डिप्रेशन है, क्योंकि वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार उचित नौकरी पाने में असमर्थ हैं। इस स्थिति को देखते हुए चीन की सरकार ने आगामी पांच वर्षों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 40 प्रतिशत है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत पैकेज पर्याप्त नहीं है और सरकार को और प्रयास करने चाहिए।

आर्थिक वृद्धि में ठहराव

चीन में बीते तीन दशकों में आर्थिक वृद्धि की दर बहुत तेज रही, लेकिन अब आर्थिक वृद्धि में ठहराव आ चुका है, जिसके कारण रोजगार के अवसर भी कम हो गए हैं। इस संकट को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को और राहत पैकेज जारी करने की आवश्यकता है, ताकि अर्थव्यवस्था को पुनः गति मिल सके और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकें। चीन की सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत है ताकि वह अपनी युवा आबादी को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके और हिंसा की घटनाओं में कमी आ सके।

20 नवंबर 1979 : मस्जिद पर 200 बंदूकधारियों ने हमलाकर सऊदी के प्रिन्स को दी थी खुली चुनौती

रियाद (ईएमएस)। 20 नवंबर 1979 को सऊदी में एक भयानक घटना हुई थी। इस दिन जुहैमान अल-उतैबी के नेतृत्व में एक हथियारबंद समूह ने बड़ी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। इस हमले ने न सिर्फ सऊदी अरब, बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को हिला दिया और सऊदी अरब की राजनीति को नया मोड़ दिया। सऊदी अरब का मक्का शहर जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। पूर्व सैनिक और धार्मिक उपदेशक जुहैमान अल-उतैबी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सऊदी शासकों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया था। वह यह मानता था कि सऊदी अरब में धार्मिक क्रांति की जरूरत है। 20 नवंबर की सुबह करीब 50,000 लोग काबा की ओर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस समय अचानक 200 हथियारबंद हमलावरों ने मस्जिद में घुसकर श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया और इमाम को गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने माइक पर ऐलान किया कि काबा और सऊदी शासन को अधर्मियों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद, हमलावरों ने बंदूकें निकालीं और मस्जिद के सभी द्वार बंद कर दिए।

सऊदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती

सुरक्षा बलों की शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, क्योंकि उस समय के क्राउन प्रिंस फहद बिन अब्दुलअजीज और अन्य प्रमुख राजनेता विदेश यात्रा पर थे। जब सऊदी पुलिस ने मस्जिद के आसपास पहुंचने की कोशिश की, तो उन पर गोलीबारी हुई और उन्हें भागना पड़ा। यह घटना न केवल सऊदी सुरक्षा बलों के लिए बल्कि पूरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। मस्जिद की बड़ी इमारत और उसकी संरचना ने इसे सुरक्षा बलों के लिए एक कठिन लक्ष्य बना दिया था।

सऊदी सेना का हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन

सऊदी सेना ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और बख्तरबंद वाहनों, तोपों और मिसाइलों का उपयोग करके हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। मस्जिद की चारों ओर सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया और विशेष बलों को भेजा गया। लगभग दो हफ्ते तक चले इस संघर्ष में सऊदी सेना और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त गोलाबारी हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। मस्जिद परिसर में पानी की कमी और शवों के सड़ने से स्थिति और भी भयावह हो गई थी। यह संकट 4 दिसंबर 1979 को समाप्त हुआ, जब सऊदी सेना ने मस्जिद को मुक्त कर लिया और विद्रोहियों को खत्म कर दिया। इस घटना ने सऊदी अरब में सुरक्षा और राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की नींव रखी। इसके बाद, सऊदी सरकार ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।

मनसुख वसावा का 'लेटर बम': जनता की बजाय ठेकेदारी में रहते हैं नेता!

अहमदाबादः किसी न किसी वजह से चर्चा में रहने वाले गुजरात बीजेपी के भरूच सांसद मनसुख वसावणो एक बार फिर 'लेटर बम' लेकर आए हैं. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि नेता जनता की सेवा करने के बजाय ठेकेदारी के काम में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं. साथ ही टेंडरों को अनुभवी एजेंसियों के बजाय नेताओं या उनके करीबी एजेंसियों द्वारा मंजूरी दी जा रही है

पत्र के मुताबिक, उन्होंने मॉडल टेंडर नियमों में बदलाव और मनरेगा 2024-25 टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को पत्र लिखा, ताकि गरीबों को रोजगार मिल सके.

अवैध काम के लिए मंत्री का जोर, मुख्यमंत्री को लिखा लेटर बम

पत्र में उन्होंने लिखा कि गुजरात राज्य में अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से रिश्तेदारों, अपने विश्वासों की एजेंसियों के टेंडरों को बड़ी चालाकी से मंजूरी देने की व्यवस्था की जा रही है. नेता जनता की सेवा करने के बजाय ठेकेदारी में अधिक रुचि ले रहे हैं। जिससे कार्यों में गुणवत्ता भी बरकरार नहीं रहती और सरकार की छवि धूमिल होती है.

दूसरी ओर, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के कामकाज में सभी जिले सरकार द्वारा दिए गए मॉडल टेंडर जारी करते हैं, लेकिन कुछ जिलों में नियमों में बदलाव करके टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई है, जिससे सचमुच गलत है. अधिकारी मनरेगा में काम कर चुकी अनुभवी एजेंसी के बजाय नेताओं या उनके करीबियों की एजेंसी के टेंडर अनुमोदन के अनुसार काम कर रहे हैं।

लिंबायत में लोगों के विरोध के बीच धार्मिक अतिक्रमण हटाया गया, एक तबेले का भी सफाया

सूरत , शहर के लिंबायत क्षेत्र के महाप्रभुनगर में सरकारी जमीन पर किए गए धार्मिक अतिक्रमण को आज हटा दिया गया हालांकि मंदिर हटाने का स्थानीय लोगों द्वारा कड़ा विरोध किए जाने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया लेकिन प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को समझाए जाने के बाद शांतिपूर्ण माहौल में डिमोलिशन की कार्यवाही की गई इसके अलावा इसी क्षेत्र के शांतिनगर की खुली जमीन पर बनाए गए तबेले को भी ढहा दिया गया दरअसल सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश और दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य की सूरत समेत राज्य की सभी महानगर पालिका द्वारा धार्मिक अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी हैं इसके अंतर्गत आज सूरत में लिंबायत क्षेत्र के महाप्रभुनगर में शेल्टर होम के आरक्षित जमीन पर 10 साल पहले किए गए धार्मिक अतिक्रमण का सफाया कर दिया गया। स्थानीय लोगों के भारी विरोध को देखते हुए पहले से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था अतिक्रमण हटाने की शुरुआत होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, परंतु प्रशासन के समझाने के बाद मामला शांतिपूर्ण माहौल में निपट गया इसके अलावा लिंबायत क्षेत्र के शांतिनगर के निकट हिंडोशी इलाके की खुली जमीन में गैरकानूनी रूप से बनाए गए तबेले को भी ढहा दिया गया। अवैध तबेले को लेकर प्रशासन को शिकायत मिली थी जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस भी भेजी आज प्रशासन ने 600 वर्ग फूट का तबेला ढहा दिया।

अब 3 वर्ष में न्याय मिल जाएगा, न्याय के लिए वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा : अमित शाह

- भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सबसे आधुनिक और तेज बनाने की शुरुआत हो चुकी

गांधीनगर , केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में मंगलवार को गांधीनगर जिले की दहेगाम तहसील के लवाड स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती समारोह को उद्घाटन किया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन 19 और 20 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में वे चौथी बार शामिल हो रहे हैं। पहली बार लखनऊ में हुए कार्यक्रम में वे सहभागी बने थे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए सतर्कता काफी जरूरी है, ताकि यह कार्यक्रम केवल मीटिंग का बहाना बनकर न रह जाए। शाह ने कहा कि देश, दुनिया और अपराध जगत में जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है, उसके मद्देनजर पुलिस को अपराध के खिलाफ लड़ने की क्षमता दिखाने वाले सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। जब पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने इस दायित्व को स्वीकार किया है, तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके नए स्वरूप और बदलाव के साथ अनुसंधान और विकास, इन दो शब्दों को जोड़कर जन-जन तक सुरक्षा पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि आने वाली चुनौतियों को समझे बिना कोई भी योजना बनाई जाए, तो उसमें सफलता कभी नहीं मिल सकती। भारत आगामी 20 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। इन 10 वर्षों में सभी को टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। किसी भी व्यवस्था में जब आगे बढ़ते हैं, तब बाधाएं आती हैं, जिसे दूर कर आगे बढ़ने पर आश्चर्यजनक सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल-2028 से पहले हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के नागरिक के रूप में गर्व करेंगे। शाह ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान भारत दुनिया के अन्य देशों के लिए अधिक चिंता का विषय था, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत कैसे इस महामारी का मुकाबला करता है, यह सोचने का विषय था। ऐसे में हमारी वैदिक परंपरा और आयुर्वेद की संस्कृति के साथ हम अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक मजबूती के साथ टिके रहे और कम से कम नुकसान के साथ फिर से खड़े भी हुए। इसके साथ ही, हमने भारत की आंतरिक सुरक्षा और न्याय प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव के बिना सफलता नहीं मिलती। आने वाले समय में भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सबसे आधुनिक और सबसे तेज बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। जिसमें तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत के बाद देश के किसी भी कोने में, किसी भी कोर्ट में अधिक से अधिक तीन वर्ष में न्याय मिल जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अब न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें लक्ष्य की शुरुआत से लेकर परिणाम यानी सफलता तक जाना है, लेकिन यह सफलता किसी अंक या आंकड़ों से साबित नहीं होती, ना ही ऐसे आंकड़ों से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पहले और आज की परिस्थिति की तुलना करने पर यह पता चलता है कि इन क्षेत्रों में अब हिंसा में 70 फीसदी की कमी आई है, यह भी हमारी बड़ी सफलता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नारकोटिक्स क्षेत्र में 5 लाख 45 हजार किलोग्राम (वर्तमान मूल्य 35 हजार करोड़ रुपए) का माल जब्त करने में हमने सफलता पाई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नारकोटिक्स के केस बढ़े है, बल्कि पिछले दस वर्ष में हमने हमारी सुरक्षा तथा पुलिस की प्रक्रिया के जरिये यह सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा चार वर्ष में काफी प्रयासों और मेहनत के बाद तीन नए आपराधिक कानून लेकर आए हैं। परिणाम व परिमाण, दोनों दृष्टि से देश की आपराधिक स्थिति पर रोक लगाने के लिए लाभकारी निर्णय भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी 17,000 पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज्ड कर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 22000 अदालतों को ई- कोर्ट के साथ जोड़ा जा चुका है और ई-प्रिजन के तहत दो करोड़ से ज्यादा कैदियों का डाटा उपलब्ध है। ई-प्रॉसीक्यूशन से डेढ़ करोड़ से ज्यादा अभियोजन का डाटा उपलब्ध है और ई-फॉरेंसिक के माध्यम से 23 लाख से अधिक फॉरेंसिक रिजल्ट्स का डाटा भी उपलब्ध है। वहीं, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस) के तहत 1 करोड़ 6 लाख लोगों का फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स उपलब्ध है। इसी प्रकार, इंडीग्रेटेड मॉनीटरिंग ऑफ टेररिज्म (आई-मोट) में 22000 आतंकवादी गतिविधियो का प्रॉसिक्यूशन पूर्ण होने तक का डेटा तथा इन्वेस्टिगेशन डेटा उपलब्ध है जबकि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर (एनआईडीएएएन) के तहत 7 लाख नार्को ऑफेंडर्स का डाटा भी है। एक लाख ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओफेंडर्स का डेटा तथा क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर में 16 लाख अलर्ट भी जनरेट हो चुके हैं। इसके साथ ही, अब जो भी नए कार्य होंगे, वे भी डेटा में जुड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रॉसिक्यूशन, पुलिस, जेल, एफएसएल, सभी को जोड़ने की व्यवस्था के साथ एक प्रक्रिया तैयार हुई है, जो अपराध से सजा और सजा से जेल तक की सारी प्रक्रियाओं से पूर्ण होती है।

इसके साथ ही उन्होंने तीन कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि 27 स्थानों पर बदलाव के जरिये जो व्याख्या तैयार की गई है, उसमें टेक्नोलॉजी बदलती रहने के बावजूद कानून की व्याख्या में अब कभी बदलाव नहीं आएगा। अंत में उन्होंने कहा कि 150 वर्ष पुराने कानून में नागरिक केन्द्र में नहीं थे, जबकि नए बने तीनों कानूनों में नागरिक व नागरिक के अधिकार ध्यान में रखे गए हैं। इन तीन कानूनों में सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ी गई हैं। इसके चलते न्याय प्रक्रिया बहुत तेज बनेगी। उन्होंने देशभर से उपस्थित महानुभावों को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि एआई का उपयोग कर एकत्र किए गए डेटा को परिणाम-उन्मुख बनाकर इससे प्राप्त विश्लेषण द्वारा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। उन्होंने इस विषय को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करने का सभी से अनुरोध किया।

शादी की लालच देकर नाबालिग लड़की से युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

सूरत , शहर के लिंबायत क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को शादी की लालच देकर उसी क्षेत्र में रहनेवाले युवक ने कई बार दुष्कर्म किया। जिसके बाद युवक ने लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया। युवक द्वारा शादी से इंकार किए जाने के बाद पीड़िता एसिड पीकर आत्महत्या की कोशिश की। इतना ही नहीं युवक ने लड़की समेत उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। आखिरकार पूरा मामला थाने पहुंच गया और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सूरत के लिंबायत क्षेत्र में रहनेवाले निलेश रणजीत चौहाण नामक युवक ने उसी क्षेत्र में रहनेवाली एक नाबालिग से पहले दोस्ती की और बाद में शादी की लालच देकर उसे प्रेमजाल फांस लिया। जिसके बाद निलेश नाबालिग लड़की को घूमने-फिरने के बहाने होटल में ले जाने लगा। निलेश चौहाण नाबालिग लड़की को सूरत के गोडादरा क्षेत्र स्थित ओयो हेटल में 7-8 दफा ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शादी की लालच देकर लड़की का यौन शोषण करने के बाद निलेश अपने वादे से मुकर गया। निलेश ने लड़की के साथ शादी करने से इंकार कर दिया। निलेश के इंकार से आहत लड़की ने एसिड पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना के बाद निलेश ने पीड़िता समेत उसके परिवार को धमकी दी कि अगर पुलिस थाने में शिकायत की तो वह सभी को जान से मार देगा। निलेश की धमकी के बाद पुलिस ने लिंबायत पुलिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी।

फर्जी डॉक्टरों का अस्पताल सील

सूरत । गुजरात के सूरत में फर्जी डॉक्टरों ने अस्पताल खोल लिया। ये डॉक्टर्स शराब के साथ पकड़े गए थे। इस अस्पताल के उद्घाटन में सूरत क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र वत्स पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे राघवेंद्र वत्स की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो हैं। मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल का न तो रजिस्ट्रेशन है न यहां अग्नि सुरक्षा उपकरण थे। उद्घाटन पर लंच हुआ। इसके अगले दिन राज्य सरकार ने अस्पताल सील कर दिया। अभी अस्पताल सील करने का कारण यहां फायर सेफ्टी के लिए कोई सिस्टम नहीं होना बताया गया है।

सोशल मीडिया के जरिए प्यार करना पड़ा महंगा, युवती की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

नवसारी , गणदेवी तहसील की एक युवती को सोशल मीडिया के जरिए अंजान युवक से प्यार करना महंगा पड़ गया। युवक ने न सिर्फ युवती के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि साढ़े तीन लाख रुपए की रकम भी ऐंठ ली। आखिरकार पीड़ित युवती ने बिलीमोरा पुलिस थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। जिसके आधार पर पुलिस ने जीत मिस्त्री नामक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। शहर में डेटिंग ऐप की मदद से जीवनसाथी ढूंढने के इच्छुक लोगों को सतर्क करनेवाली घटना सामने आई है। जिसमें एक लड़की को सोशल मीडिया के जरिए जीत मिस्त्री नामक एक युवक से प्यार हो गया। जिसके बाद जीत मिस्त्री ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं जीत मिस्त्री ने युवती को केवल अपनी हवस का शिकार नहीं बनाया बल्कि उससे करीब साढ़े लाख रुपए तक ऐंठ लिए। युवती से लिए गए रुपए लौटाने की जीत मिस्त्री की नीयत नहीं थी। युवती ने जब जीत से अपने रुपए वापस मांगे तो जीत मिस्त्री पीड़िता को नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। धमकी के बाद युवती ने हिम्मत जुटाई और बिलीमोरा पुलिस स्टेशन में जीत मिस्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। जिसके आधार पर बिलीमोरा पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी जीत मिस्त्री को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।

शिव जी का जलाभिषेक करते अचानक ढेर हुआ श्रद्धालु, हार्ट अटैक से मौत की आशंका

वलसाड (ईएमएस) शहर के पारनेरा क्षेत्र के एक मंदिर में जलाभिषेक कर रहा एक श्रद्धालु अचानक वहीं ढेर हो गया। मंदिर में मौजूद अन्य लोग तुरंत श्रद्धालु को निकट अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वलसाड के पारनेरा इलाके में स्थित भगवान महादेवजी के मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। शहर की अतुल सोसायटी में रहने वाले किशोरभाई भी रोजाना महादेव मंदिर जाते थे। रोज की भांति किशोरभाई आज भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए। मंदिर में आरती के बाद शिव जी का अभिषेक करते समय किशोरभाई अचानक गिर पड़े। घटना के बाद मंदिर में उपस्थित अन्य लोगों ने किशोरभाई को तुरंत निकट अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने किशोरभाई को मृत घोषित कर दिया। किशोरभाई की मौत का कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आशंका है अभिषेक करते समय अचानक दिल का दौरा पड़ने से किशोरभाई की मौत हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

भाजपा नेता के बेटे की हत्या के मामले में कांस्टेबल और एलआरडी जवान सस्पैंड

वडोदरा , भाजपा नेता और पूर्व पार्षद रमेश परमार के बेटे तपन परमार की हत्या के मामले में दो एक कांस्टेबल और एलआरटी जवानों को सस्पैंड कर दिया गया है। ये दोनों घटना के वक्त एसएसजी अस्पताल में मौजूद थे। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बिता दें कि तपन परमार की हत्या के मामले में बाबर समेत 6 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी बाबर के खिलाफ 25 जितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। वडोदरा में पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या को लेकर मामला काफी गरमा गया है। इस मामले में लापरवाही के चलते दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। दोनों पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। एसएसजी अस्पताल में सुरक्षा में मौजूद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि आरोपी ने पुलिस की मौजूदगी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक तपन के परिवार ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में तपन की हत्या होने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाई गई, जबकि उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और अन्य को चाकू मार दिया। मृतक के परिवार ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

भोजपरा में विदेशी शराब समेत 20.90 लाख का माल जब्त, दो आरोपी भी गिरफ्तार

राजकोट (ईएमएस) राजकोट एलसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोजपरा में विदेशी शराब समेत रु. 20.90 लाख से अधिक माल जब्त कर लिया। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इस मामले के अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने की दिशा में कोशिशें तेज कर दी। जानकारी के अनुसार राजकोट एलसीबी ने गोंडल राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोजपरा गांव के बाहरी इलाके में छापेमारी की। और श्री जोगमाया ने गोदाम-3 से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब समेत रु. 20,90,856/- के माल के साथ कैलाश बाबूलाल जगमाल और जालाराम भीखाराम उदाराम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों प्रकाश उर्फ सत्या बिश्नोई, नारायण सिंह पदम सिंह और कार के मालिक को गिरफ्तार करने की कवायद तेज कर दी है।

भरूच में खड़े ट्रक से भिड़ी ईको कार, 6 की मौत, कार को कटर से काटकर निकालना पड़े शव

भरूच(ईएमएस)। भरूच के जंबूसर-आमोद रोड पर सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। कार में कुल 10 लोग सवार थे इसमें दो बच्चों और दो महिलाओं सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। शवों को निकालने के लिए कटर से कार को काटना पड़ा। मृतकों में सपनाबेन जयदेव गोहिल,जयदेव गोविंदभाई गोहिल,कीर्तिकाबेन अर्जुनसिंह गोहिल,हंसाबेन अरविंद जादव,संध्याबेन अरविंद जादव,विवेक गणपत परमार शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि यहां एक ईको कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा भरूच के जंबूसर-आमोद रोड पर सोमवार देर रात हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि ईको कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को वहां 4 लोग घायल अवस्था में मिले, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जंबूसर पुलिस ने मृतकों क शव पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल पहुंचा दिये हैं। बताया जा रहा है कि इको गाड़ी में सवार सभी लोग जंबूसर के वेडच और पांचकड़ा गांव के रहने वाले हैं। सभी शुक्लतीर्थ में चल रहे मेले से लौट रहे थे। गाड़ी मे 10 लोग सवार थे, जिसमें से 6 की मौत हो गई।

गैर किसान खरीद सकेंगे कृषि भूमि का कानून आया तो कांग्रेस करेगी विरोध :अमित चावड़ा

अहमदाबाद (ईएमएस) कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने सरकार की चेतावनी है कि अगर वह गैर किसान खरीद सकेंगे कृषि भूमि कानून लाएगी तो कांग्रेस का उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। कांग्रेस कृषि और किसानों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक इस कानून का जमकर विरोध करेगी। कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने आज पत्रकार परिषद में कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश-प्रदेश की तरक्की में किसान और खेती का बड़ा योगदान है। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र जो कृषि के साथ ही पशुपालन और सहकारी गतिविधियों से जुड़े हैं जो पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि का एक माध्यम है। अमित चावड़ा ने कहा कि राज्य सरकार गुजरात भूमि कानून में संशोधन करने जा रही है। मीना समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है ताकि गैर-किसान भी कृषि भूमि के मालिक बन सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम राज्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। वर्षों से खेती और किसानों को बर्बाद करने की जो सुनियोजित साजिश चल रही है और अब उसे लागू करने की कोशिशें तेज हो गई है। पिछले 30 वर्षों में सरकारी नीतियों के कारण कृषि भूमि की बिकी हैं, किसानों की संख्या में और कृषि भूमि में कमी आई है। वहीं कृषि भूमि पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में गैर किसानों को फर्जी तरीके से किसान बनाने का नेटवर्क गुजरात में चल रहा है। जिसके आधार पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम सरकार को अनुरोध के साथ चेतावनी भी देते हैं कि ऐसा कोई भी संशोधन करने से पहले गुजरात की जनता और राजनीतिक दलों से सलाह लें। अन्यथा जमीन कानून में संशोधन से गैर-किसान भी कृषि भूमि खरीद सकेंगे। इस संशोधन का किसान, किसान संगठन और सामाजिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। अमित चावड़ा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार भूमि कानून में संशोधन कर गैर किसान भी कृषि भूमि का मालिक बन सकेंगे का प्रावधान करती है कांग्रेस कृषि और किसानों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक जमकर विरोध करेगी।

आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा व कानून-व्यवस्था मजबूत होः मुख्यमंत्री

गांधीनगर , मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक के अमृत काल में भारत हर क्षेत्र में सर्वप्रथम, सक्षम व आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने की पहली शर्त है कि देश की सीमाएँ सुरक्षित हों और देश में आंतरिक सुरक्षा व कानून-व्यवस्था मजबूत हों। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल गांधीनगर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि यह सभी के लिए गर्व की बात है कि देश की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व देश के कर्मठ गृह मंत्री अमित शाह पूरी निष्ठा के साथ संभाल रहे हैं। अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कानून-व्यवस्था एवं पुलिस बल में अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साइंटिफिक पुलिसिंग पर बल दिया गया है, जिसके कारण क्राइम इन्वेस्टिगेशन तथा डिटेक्शन की पद्धति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुलिस बल के मॉडर्नाइजेशन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व गृह मंत्री अमित शाह के विजन के कारण क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम (सीसीटीएनएस) तथा इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) समग्र देश में प्रभावी ढंग से लागू हुए हैं। इस व्यवस्था के कारण एक ही बार पुलिस केस के डेटा से पुलिस, फोरेंसिक, प्रॉसिक्यूशन, कोर्ट तथा प्रिजन सभी एक्सेस कर सकते हैं और इससे जाँच तेज होती है।

कच्छ के बाद अब दक्षिण गुजरात के वलसाड में भूकंप का झटका

अहमदाबाद (ईएमएस) दक्षिण गुजरात के वलसाड में भूकंप के झटके से लोगों में दहशत फैल गई। हांलाकि भूकंप की तीव्रता मामूली होने से कोई नुकसान की खबर नहीं है। वलसाड जिले के धरमपुर तहसील में भूकंप का झटका महसूस किया गया। सुबह करीब 11 बजे के आसपास 2.5 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र वलसाड जिले के धरमपुर तहसील के मोळाआंबा गांव के पास दर्ज किया गया। इससे पहले कल कच्छ जिले के रापर समेत वागड़ इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जिसमें 4.0 तीव्रता के भूकंप से वागड़ की जमीन थर्रा उठी। कच्छ में रात 8 बजकर 18 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिससे लोग घर से बाहर की ओर दौड़ पड़े। भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप के झटके कच्छ जिले के रापर से लेकर भचाऊ, गांधीधाम तक के इलाकों में महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र रापर से 26 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया। गौरतलब है 4 दिन पहले उत्तरी गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जिसमें पाटण, पालनपुर, मेहसाणा और अहमदाबाद समेत कई शहरों में लोगों ने 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया। भूकंप का केंद्र पाटण से 13 किमी दूर चाणस्मा तहसील के सेवाला गांव में दर्ज किया गया।

एसएमसी ने जुए के अड्डा पर रेड 30 जुआरियों को पकड़ा, 6.58 लाख का माल जब्त

सुरेन्द्रनगर (ईएमएस) स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) ने सुरेन्द्रनगर में छापा मारकर एक बड़े जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने करीब 30 जुआरियों समेत 6.58 लाख से ज्यादा के माल जब्त कर लिया। खास बात है कि जांच में पता चला कि यह जुए का अड्डा वडोदरा के एसीबी पीआई का भाई चलाता था। जानकारी के मुताबिक सुरेन्द्रनगर जिले के पाटडी तहसील के वेलनाथनगर में एक आवासीय घर जुए का अड्डा चल रहा था। पूर्व सूचना के आधार पर एसएमसी ने घर में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा। एसएमसी टीम को देखते ही घर के दरवाजे बंद कर लिए गए। हांलाकि पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और जुआ खेल रहे 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें पांच महिलाएं भी शामिल थीं। एसएमसी टीम ने छापेमारी के दौरान वाहन, मोबाइल फोन, नकदी समेत कुल 6.58 लाख रुपये जब्त किये। बताया जाता है कि पाटडी का जुए का अड्डा वडोदरा एसीबी पीआई के भाई द्वारा चलाया जाता था। पुलिसकर्मी के भाई किरण ठाकोर पर इस जुए के अड्डे को चलाने का आरोप है।

गुजरात में नगर पालिकाओं की आर्थिक हालत खस्ता, इतने करोड़ के बिजली बिल हैं बकाया!

गांधीनगरः गुजरात राज्य की नगर पालिकाओं की वित्तीय हालत बेहद खराब हो गई है. जिसमें प्रदेश की अधिकांश नगर पालिकाओं का खजाना खाली है। राज्य की नगर पालिकाओं की खराब वित्तीय स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास बिजली का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं हैं. एक रिपोर्ट सामने आई है कि गुजरात की 57 नगर पालिकाओं को अभी भी करोड़ों रुपये का बिजली बिल चुकाना बाकी है.

311 करोड़ बिजली बिल बकाया

एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की 57 नगर पालिकाओं ने 311 करोड़ रुपये के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. जिसके चलते इस नगर पालिका की स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन कट सकता है। राजस्व घटने से नगर पालिकाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल समेत विभिन्न करों की वसूली में नगर निगम की व्यवस्था सख्त नहीं होने से प्रशासन का राजस्व घट रहा है. वहीं स्थानीय स्वशासन चुनाव को देखते हुए जन प्रतिनिधि भी सख्ती से वसूली पर जोर देते हैं. इन सब कारणों से नगर पालिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। अहम बात यह है कि टैक्स की रकम बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है. लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

इसके अलावा, नगर वित्त बोर्ड राज्य में नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए परियोजना-आधारित ऋण प्रदान करता है। प्रदेश की इन नगर पालिकाओं की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें सरकार को प्रस्ताव देकर और 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेकर बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है. यदि बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थ नगर पालिकाएं ऐसा नहीं करती हैं तो स्ट्रीट लाइट और पानी के बोर के कनेक्शन काट दिए जाने की आशंका है। जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

10 साल में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा 70 फीसदी कम हुईः अमित शाह

गांधीनगरः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं. सोमवार को घाटलोडिया विधानसभा में 'नव वर्ष स्नेह मिलन' समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के बाद आज राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में भाग लिया। जिसमें उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा को 70 फीसदी तक कम किया है. अगले दशक में भारत की न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे वैज्ञानिक और तेज़ होगी।

शाह ने कहा, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को सबसे अधिक अस्थिर माना जाता है। लेकिन आज तीनों इलाकों में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है. पिछले दशक के आंकड़ों की तुलना में हिंसा में 70 फीसदी की कमी आई है. गृह मंत्री ने कहा, तीन नए कानूनों के लागू होने से अब किसी भी थाने में प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराने पर तीन साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा.

भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और बीएसए को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को बदलने के लिए पेश किए गए थे। ये सुधार भारत की न्याय प्रणाली को मजबूत और तेज़ बनाएंगे। जिससे इस व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सकेगा।

भारतीय कोस्टगार्ड ने पाकिस्तानी जहाज से मछुआरों को बचाया

अहमदाबाद(ईएमएस)। भारतीय नौसेना ने समुद्री सीमा रेखा के निकट समुद्र में पीछा करने के बाद पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के एक जहाज से सात भारतीय मछुआरों को बचा लिया। अधिकारियों ने बताया कि तटरक्षक बल को रविवार दोपहर को मछली पकड़ने के लिए निषिद्ध क्षेत्र (एनएफजेड) के पास काम कर रही एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव से संकटकालीन संकेत प्राप्त हुआ, जिसके बाद बचाव अभियान के लिए एक जहाज भेजा गया। 17 नवंबर 2024 की दोपहर साढ़े तीन बजे भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजी अग्रिम के पास एक इमरजेंसी कॉल आई। यह एक डिस्ट्रेस कॉल थी यानी मदद के लिए बुलावा।

आईसीजी अग्रिम ने फुल स्पीड में जाकर पाकिस्तानी जहाज नुसरत को रोका। दो घंटे तक चूहे-बिल्ली की तरह समंदर में रेस चलती रही। इसके बाद पाकिस्तानी जहाज को कहा कि भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया जाए। आखिरकार धमकी और समझाइश काम आई। पाकिस्तानी जहाज ने मछुआरों और नाव को छोड़ दिया। लेकिन कालभैरव नाव टूट गई थी। जिसकी वजह से वह समंदर में ही डूब गई।

एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

गांधीनगर, 19 नवंबर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें स्मृति चिह्न के रूप में कच्छ की मशहूर हस्त कलाकृति का उपहार दिया। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह जानने में रुचि दिखाई कि कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात विकास का रोल मॉडल बना। इतना ही नहीं, उन्होंने डबल इंजन की सरकार की दोगुनी विकास गति के लिए मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आयोजित फिलाटेली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

गांधीनगर , केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर डाक प्रभाग द्वारा दांडी कुटीर में आयोजित जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी 'फिलाविस्टा 2024' का मंगलवार को उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। अमित शाह, भूपेन्द्र पटेल तथा आमंत्रितों ने उद्घाटन के बाद विशिष्ट एवं दुर्लभ पोस्टल स्टाम्प्स की इस रुचिप्रद प्रदर्शनी को देखा। प्रदर्शनी की मुलाकात के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने गांधीनगर पोस्टल डिवीजन के 'फिलाविस्ट 2024' अंतर्गत 'गांधीनगर में स्थापत्य कला' थीम पर आधारित विशेष पोस्टल कवर का अनावरण भी किया। इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, राज्य के मुख्य सचिव राज कुमार, गांधीनगर जिला कलेक्टर मेहुल दवे, गुजरात के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल गणेश सालवेश्वरकर तथा उत्तर गुजरात जोन के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव सहित डाक विभाग के उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे। इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दांडी कुटीर में बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रदर्शनी नागरिकों के लिए 19 व 20 नवंबर को सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुली हेगी। फिलाटेली प्रेमियों को यह प्रदर्शनी दुर्लभ एवं आकर्षक स्टाम्प्स का एक विशेष कलेक्शन देखने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी।

पश्चिम रेलवे ने 14 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से किया सम्मानित

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने पश्चिम रेलवे के 14 कर्मचारियों को सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए प्रधान कार्यालय, चर्चगेट में सम्मानित किया। इन कर्मचारियों को सितम्बर एवं अक्टूबर, 2024 के दौरान ड्यूटी में उनकी सतर्कता तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने में उनके योगदान और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया। इन 14 कर्मचारियों में मुंबई सेंट्रल मंडल से 04, अहमदाबाद, भावनगर एवं वडोदरा मंडल प्रत्येक से 03 जबकि राजकोट मंडल से 01 कर्मचारी शामिल है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मिश्र ने सम्मानित किए गए कर्मचारियों की सतर्कता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सभी कर्मचारियों के लिए अनुकरणीय आदर्श हैं। सम्मानित किए गए कर्मचारियों ने संरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेल एवं ट्रैक फ्रैक्चर का पता लगाना, अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगाना, मानव जीवन को बचाना, कोचों में पाए जाने वाले धुएं को बुझाना, ब्रेक बाइंडिंग, लटकती वस्तुओं का पता लगाना आदि जैसे संरक्षा से संबंधित कार्यों को करते हुए ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने में उत्साह और प्रतिबद्धता दिखाई। पश्चिम रेलवे को इन सभी पुरस्कृत कर्मचारियों पर गर्व है जिन्होंने अपनी त्वरित कार्रवाई और सतर्कता से किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने में मदद की।

मालिक, मुद्रक-प्रकाशक व सम्पादक : लक्ष्मीचन्द जी. अग्रवाल द्वारा ब्रिजाशा ऑफसेट, सरसपुर, अहमदाबाद में मुद्रित करवाकर, स्वेतप्रित बिल्डिंग, खासवाड़ी, बहुचराजी रोड़, वड़ोदरा से प्रकाशित किया। प्रातःकालीन E-mail: janhitaishi@yahoo.co.in Mob.9375504122 R.N.I. 64278/96